● वर्ष-3
● अंक-80
रायपुर, शुक्रवार
10 नवंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› हिंदू पौराणिक कथाओं के...

छत्तीसगढ़ की सरकार ने महादेव के नाम पर सट्टा शुरू कर दिया: अमित शाह

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चंद्रयान के उतरने वाले स्थान का नाम 'शिव शक्ति' रखकर भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्ति की लेकिन छत्तीसगढ़ की (कांग्रेस) सरकार ने महादेव के नाम पर सट्टा शुरू कर दिया। शाह ने जशपुर जिले के बगीचा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद, पांच वर्ष के भीतर राज्य से नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार है, मोदी ने चंद्रयान भेजा चंद्रमा पर, और जहां चंद्र यान उतरा, उस जगह का नाम 'शिव शक्ति पॉइंट' रख कर उन्होंने भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या किया?

महादेव ऐप से जोड़कर सट्टा खोलने का काम किया। शर्म करें, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। शाह राज्य में कथित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाले का

जिक्र कर रहे थे। उन्होंने राज्य सरकार पर चावल घोटाला और अन्य घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा, यहां का बच्चा बच्चा कह रहा है सट्टे पे सट्टा कौन करा रहा, भूपेश कक्का। भूपेश बघेल को राज्य में कका कहा जाता है। भाजपा नेता ने पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार के दौरान देश के असुरक्षित हाथों में होने का आरोप लगाया और कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गयी। उन्होंने कहा, जब कांग्रेस की सरकार थी तब रोज पाकिस्तान से आतंकवादी घुस कर हमारे यहां धमाके करते थे। जब मोदी सरकार बनी तब आतंकवादियों ने उरी और पुलवामा में भी हमला करने की कोशिश की लेकिन 10 दिनों के भीतर ही पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों का सफाया किया गया।''

शाह ने कहा, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के कुछ जिले अभी भी नक्सलवाद का दंश भोग रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप डबल इंजन की सरकार (केंद्र और राज्य में भाजपा) बनाइए, पांच साल में हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। उन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बगीचा क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया और कहा कांग्रेस सरकार 70 साल से राम जन्मभूमि को अटका, भटका, लटका रही थी। नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी करने वाले हैं। शाह ने कहा, राहुल बाबा हमें कहते थे तिथि कब बताओगे ? लो राहुल जी, तिथि बता दी ... 22 जनवरी से 24 जनवरी, मुझे मालूम है कि आप दर्शन करने नहीं जाएंगे। बगीचा वाले सभी लोग तो जाएंगे ना? उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ। ''हम आदिवासी भाई-बहनों का उनकी सहमति के बिना धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे और उनकी रक्षा करेंगे।

चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों पर हमला

रुद्र कुमार के काफिले पर पथराव

रायपुर। बेमेतरा जिले के विधानसभा क्षेत्र नवागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी गुरु रूद्र कुमार के काफिले पर पथराव हुआ है। वे अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार करने ग्राम झाल गए थे। इसी दौरान वापसी में गांव के बाहर रात करीब 10 बजे कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया। इससे गुरु रुद्रकुमार की गाड़ी का शीशा टूट गया। उनके काफिले में तीन गाड़ियां चल रही थीं। बेमेतरा की एसपी भावना गुप्ता ने बताया कि नवागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार के काफिले पर कुछ लोगों ने उस समय हमला किया जब वह एक कार्यक्रम में थे। मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अचानक अंधेरे में हुए पथराव से गाड़ियों के शीशे टूट गए। इस हमले के बाद उनके समर्थक नवागढ़ थाना में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। इस मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। फिलहाल गुरु रुद्रकुमार पूर्णत: स्वस्थ्य हैं। वहीं उनका आज गुरुवार का प्रचार प्रसार का शेड्यूल भी देर रात 12 बजे जारी किया गया है। आज वे नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 13 गांवों में जनसंपर्क करेंगे। इस बार वे बेमेतरा जिले के नवागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक चुनाव में उनकी दो बार विधानसभा सीट बदल चुकी है।

बृजमोहन अग्रवाल के साथ मारपीट

रायपुर। वरिष्ठ नेता और रायपुर दक्षिण से विधायक बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर गुरुवार देर शाम हमला कर दिया गया। इस दौरान उनका कॉलर पकड़कर घसीटा और मारपीट की। बृजमोहन अग्रवाल प्रचार के लिए बैजनाथ पारा पहुंचे थे। अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि एजाज ढेबर और अनवर ढेबर के लोग उनकी हत्या करवाना चाहते थे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने इसे प्रायोजित बताया है। इसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक कोतवाली थाने पहुंचे हैं और घेराव कर दिया है। वे कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कोतवाली में इस समय करीब डेढ़ से दो हजार लोग जमा हैं। विधायक अग्रवाल ने कहा कि जब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होगी, यहीं कोतवाली में बैठकर प्रदर्शन करते रहेंगे। कोतवाली में सैकड़ों की संख्या में समर्थक एकत्र हैं और हमलावरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। समर्थकों आरोप है कि बृजमोहन अग्रवाल प्रचार के लिए बैजनाथ पारा पहुंचे थे। यहां के मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड में प्रचार के दौरान मदरसे के पास कुछ लोग बृजमोहन के पास आए। उन्होंने कहा कि इस वार्ड में घुसने की हिम्मत कैसे हुई और उन्हें धक्का दे दिया। इस बीच जब तक उनके समर्थक आते, तब तक वे बृजमोहन अग्रवाल से मारपीट कर भाग चुके थे।

नुकूल मौसम और समय पर बारिश से कश्मीर में केसर की फसल का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। इस वर्ष, जलवायु की स्थिति मध्यम थी और घाटी में अच्छी मात्रा में वर्षा हुई, जिसके कारण केसर उत्पादकों को पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष संतोषजनक और गुणवत्तापूर्ण केसर उत्पादन की उम्मीद है।

सांसद का दावा, लोकसभा में उठा चुका हूं मुद्दा: पांडे

नईदिल्ली। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार लगातार जारी है। इन सबके बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला करने का भाजपा को बड़ा मौका मिल गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव सट्टाबाजी ऐप के प्रवर्तकों से 508 करोड रुपए लेने का आरोप लगा है। हालांकि, कांग्रेस लगातार इसको खारिज करती रही है। इन सब के बीच राजनांदगांव से भाजपा सांसद संतोष पांडे ने इस मुद्दे को काफी पहले लोकसभा में उठाया था। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यमों से बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मैं संसद में पहले ही इस मामले को उठा चुका हूं कि किस तरीके से राज्य में सट्टाबाजी जोरों पर हो रही है।

संतोष पांडे ने बताया कि मैंने एक वर्ष पूर्व ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के महादेव सट्टा ऐप में संलिप्तता की बात माननीय लोकसभा सदन के समक्ष रखा था। कांग्रेस के कुशासन में प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली

कांग्रेस सरकार के राज में हुए महादेव सट्टा ऐप, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, गोठान घोटाला ने प्रदेश को बदहाली के गर्त में धकेल दिया है। भाजपा इसको लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। कथित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाले का जिक्र करते हुए आज अमित शाह ने कहा कि महादेव ऐप से जोड़कर सट्टा खोलने का काम किया। शर्म करें, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते।

कांग्रेस ने महादेव ऐप के मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगाए गए आरोपों की पृष्ठभूमि में बुधवार को निर्वाचन आयोग का रुख किया और कहा कि विधानसभा चुनाव के समय केंद्रीय एजेंसी की 'मनमानी' बंद होनी चाहिए और उसे संरक्षण मिलना चाहिए। पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर प्रतिवेदन दिया और यह दावा भी किया कि चुनाव आते ही केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है ताकि कांग्रेस को चुनावी रण में समान अवसरों से उपेक्षित रखा जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दावा किया था कि उसने पैसे का लेन-देन करने वाले एक व्यक्ति का बयान दर्ज किया है, जिसने आरोप लगाया है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तकों ने बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

प्रमुख समाचार

मोदी डिग्री विवाद : अरविंद केजरीवाल को लगा झटका

नईदिल्ली। गुजरात हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत के 31 मार्च के फैसले को चुनौती दी गई थी कि गुजरात

विश्वविद्यालय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 2016 के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को पलटने के बाद केजरीवाल ने एक समीक्षा याचिका दायर की थी, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को मोदी की डिग्री का विवरण प्रदान करने का आदेश दिया गया था। सीआईसी का आदेश सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत केजरीवाल के एक आवेदन पर पारित किया गया था। इस अदालत की राय है कि एक बार जब किसी विशेष वादी की सुनवाई के बाद सक्षम अदालत द्वारा निष्कर्ष दर्ज किया जाता है, तो वादी केवल अपना कानूनी उपाय और कानून का सहारा ले सकता है जो कानून में उपलब्ध हो सकता है। न्यायाधीश बीरेन वैष्णव ने गुरुवार को 18 पेज के आदेश में कहा कि अदालत इस बात से अवगत है कि समीक्षा की मांग करना कानून में उपलब्ध एक उपाय है।

4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र

नईदिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होने वाला है और क्रिसमस से पहले समाप्त हो जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद

जोशी ने कहा कि सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। जोशी ने आगे कहा कि शीतकालीन सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी और यह 19 दिनों तक चलेगा। उन्होंने कहा, अमृत काल के बीच मैं सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा का इंतजार कर रहा हूं। सितंबर में आयोजित विशेष सत्र के बमुश्किल दो महीने बाद शीतकालीन सत्र निर्धारित किया गया है। चर्चा के लिए पेश किए गए पांच विधेयकों में से विशेष सत्र के दौरान केवल एक विधेयक - नारी शक्ति वंदन अधिनियम - पारित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अपनी मंजूरी पर हस्ताक्षर करने के बाद 28 सितंबर को यह विधेयक अधिनियम बन गया, जिससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33त्न आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। विशेष सत्र से पहले, अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार केवल भारत के उपयोग से संबंधित एक विधेयक को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी।

आचार समिति ने मोइत्रा के निष्कासन की अनुशंसा की

नईदिल्ली। लोकसभा की आचार समिति ने 'रिश्वत लेकर प्रश्न पूछने' संबंधी आरोपों के मामले में बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा को संसद के निचले सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। लोकसभा सचिवालय के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के मुताबिक, संभवत- यह पहली बार है कि लोकसभा की आचार समिति ने किसी सांसद के निष्कासन की अनुशंसा की है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली समिति ने आज बैठक की जिसमें समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। बैठक के बाद सोनकर ने संवाददाताओं से कहा कि समिति के छह सदस्यों ने रिपोर्ट को स्वीकार करने का समर्थन किया और चार ने इसका विरोध किया। विरोध करने वाले विपक्षी सांसदों ने समिति की अनुशंसा को 'पूर्वाग्रत से युक्त' और 'गलत' बताया।सूत्रों के मुताबिक, माना जा रहा है कि कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने रिपोर्ट के समर्थन में वोट दिया है। वह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस छोड़ चुके हैं। आचार समिति मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की है।

चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत पर सुनवाई स्थगित

नईदिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने फाइबरनेट मामले में अग्रिम जमानत का आग्रह करने वाली तेदेपा प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को 30 नवंबर तक के लिए

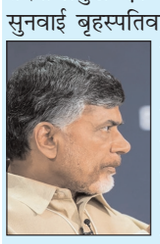

स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले को यह कहते हुए टाल दिया कि कौशल विकास घोटाला मामले में नायडू द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर फैसला अदालत की दीपावली की छुट्टियों के बाद आने की संभावना है। पीठ ने कहा, उसी याचिकाकर्ता की एक और याचिका है जिसमें कुछ मुद्दे हैं जिसमें इस पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले को 30 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, नायडू की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि यह प्रारंभिक व्यवस्था जारी रहनी चाहिए कि पुलिस नायडू को गिरफ्तार नहीं करेगी। शीर्ष अदालत ने पूर्व में आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा था कि कौशल विकास घोटाला मामले में याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक फाइबरनेट मामले में नायडू को गिरफ्तार न किया जाए।

जनप्रतिनिधियों के मुकदमों के लिए पीठ गठित करें : सुको

नईदिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक अहम फैसले के तहत सभी उच्च न्यायालयों को जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों की निगरानी के लिए एक विशेष पीठ गठित

करने और स्वत- संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने का निर्देश दिया, ताकि उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जन प्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के अनुरोध वाली अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों को कई निर्देश जारी किए। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके लिए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए निचली अदालतों को एक समान दिशा-निर्देश देना मुश्किल होगा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था में कहा गया है कि उच्च न्यायालय कानून निर्माताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमों की निगरानी के लिए एक विशेष पीठ का गठन करेंगे, जिसकी अध्यक्षता या तो मुख्य न्यायाधीश या फिर उनके (मुख्य न्यायाधीश के) द्वारा नामित पीठ द्वारा की जाएगी।

शोधकर्ताओं की चेतावनी

2026 तक एआई को प्रशिक्षित करने का डेटा ख़त्म हो सकता है

जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अपनी लोकप्रियता के चरम पर पहुंच रही है, शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि उद्योग में प्रशिक्षण डेटा खत्म हो सकता है - वह ईंधन जो शक्तिशाली एआई सिस्टम चलाता है। यह एआई मॉडल, विशेष रूप से बड़े मॉडल के विकास को धीमा कर सकता है, और एआई क्रांति के प्रक्षेपवक्र को भी बदल सकता है। लेकिन वेब पर डेटा की मात्रा को देखते हुए, डेटा की संभावित कमी एक मुद्दा क्यों है? और क्या जोखिम से निपटने का कोई तरीका है? एआई के लिए उच्च गुणवत्ता वाला डेटा क्यों महत्वपूर्ण है? शक्तिशाली, सटीक और उच्च गुणवत्ता वाले एआई एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने के लिए हमें बहुत सारे डेटा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, चैटजीपीटी को 570 गीगाबाइट टेक्स्ट डेटा या लगभग 300 अरब शब्दों पर प्रशिक्षित किया गया था।इसी तरह, स्थिर प्रसार एल्गोरिथ्म (जो डीएएलएल-ई, लेंसा और मिडजर्नी जैसे कई एआई छवि-जनरेटिंग ऐप्स के पीछे है) को 5.8 अरब छवि-पाठ जोड़े वाले एलआईएओएन-5बी डेटासेट पर प्रशिक्षित किया गया था। यदि किसी एल्गोरिदम को अपर्याप्त मात्रा में डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, तो यह गलत या निम्न गुणवत्ता वाले आउटपुट उत्पन्न करेगा। प्रशिक्षण डेटा की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है. निम्न-गुणवत्ता वाला डेटा जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट या धुंधली तस्वीरें प्राप्त करना आसान है, लेकिन उच्च प्रदर्शन वाले एआई मॉडल

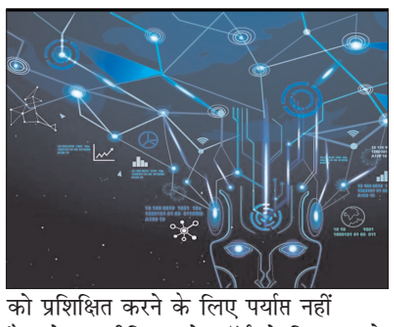

को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से लिया गया टेक्स्ट पक्षपातपूर्ण भ्रामक हो सकता है, या इसमें दुष्प्रचार या अवैध सामग्री शामिल हो सकती है जिसे मॉडल द्वारा दोहराया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, जब माइक्रोसॉफ्ट ने ट्विटर सामग्री का उपयोग करके अपने एआई बॉट को प्रशिक्षित करने की कोशिश की, तो उसने नस्लवादी और महिलाविरोधी आउटपुट उत्पन्न करना सीख लिया। यही कारण है कि एआई डेवलपर्स किताबों से पाठ, ऑनलाइन लेख, वैज्ञानिक पेपर, विकिपीडिया और कुछ फ़िल्टर की गई वेब सामग्री जैसी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की तलाश करते हैं। गूगल असिस्टेंट को अधिक संवादात्मक बनाने के लिए स्व-प्रकाशन साइट स्मैशवर्ड्स से लिए गए 11,000 रोमांस उपन्यासों पर प्रशिक्षित किया गया था। क्या हमारे पास पर्याप्त डेटा है? एआई उद्योग बड़े डेटासेट पर एआई सिस्टम का प्रशिक्षण कर रहा है, यही कारण है कि अब हमारे पास चैटजीपीटी या डीएएलएल-ई 3 जैसे उच्च प्रदर्शन वाले मॉडल हैं। साथ ही, शोध से पता चलता है कि ऑनलाइन डेटा स्टॉक एआई को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए गए डेटासेट की तुलना में बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं।

पिछले साल प्रकाशित एक पेपर में, शोधकर्ताओं के एक समूह ने भविष्यवाणी की थी कि अगर मौजूदा एआई प्रशिक्षण रुझान जारी रहा तो हमारे पास 2026 से पहले उच्च गुणवत्ता वाला टेक्स्ट डेटा खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि निम्न-गुणवत्ता वाला डेटा 2030 और 2050 के बीच समाप्त हो जाएगा, और निम्न-गुणवत्ता वाला छवि डेटा 2030 और 2060 के बीच समाप्त हो जाएगा। लेखांकन और परामर्श समूह पीडब्ल्यूसी के अनुसार, एआई 2030 तक विश्व अर्थव्यवस्था में 15.7 खरब अमेरिकी डॉलर तक का योगदान दे सकता है। लेकिन प्रयोग करने योग्य डेटा ख़त्म होने से इसका विकास धीमा हो सकता है। क्या हमें चिंतित होना चाहिए? हालाँकि उपरोक्त बिंदु कुछ एआई प्रशंसकों को चिंतित कर सकते हैं, स्थिति उतनी बुरी नहीं हो सकती जितनी दिखती है।

भविष्य में एआई मॉडल कैसे विकसित होंगे, इसके बारे में कई चीजों के बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है, साथ ही डेटा की कमी के जोखिम को दूर करने के कुछ तरीके भी हैं। एआई डेवलपर्स के लिए एल्गोरिदम में सुधार करने का एक अवसर है ताकि वे अपने पास पहले से मौजूद डेटा का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकें। संभावना है कि आने वाले वर्षों में वे कम डेटा और संभवत: कम कम्प्यूटेशनल शक्ति का उपयोग करके उच्च प्रदर्शन वाले एआई सिस्टम को प्रशिक्षित करने में सक्षम होंगे। इससे एआई के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी मदद मिलेगी।

एक अन्य विकल्प सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए सिंथेटिक डेटा बनाने के लिए एआई का उपयोग करना है। दूसरे शब्दों में, डेवलपर्स अपने विशेष एआई मॉडल के अनुरूप क्यूरेट किए गए डेटा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं।कई परियोजनाएं पहले से ही सिंथेटिक सामग्री का उपयोग कर रही हैं, जो अक्सर मोस्टली एआई जैसी डेटा-जनरेटिंग सेवाओं से प्राप्त होती हैं।

चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ और ओड़िशा के आबकारी अमलों की अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक

महासमुंद। आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन नवम्बर 2023 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ और ओड़िशा राज्यों के सीमावर्ती जिलों के आबकारी अमलों की सीमा समन्वय बैठक वर्चुअल माध्यम से बुधवार को संपन्न हुई। बैठक में उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता रायपुर अनिमेष नेताम, उपायुक्त नार्दन डिवीजन ओड़िशा श्री राजेंद्र बोथरा और बिलासपुर उपायुक्त श्री नोहर सिंह ठाकुर ने दोनों राज्यों के विभागीय अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया। निर्वाचन अवधि में सीमावर्ती इलाकों की जांच चौकियों में दोनों राज्यों की ओर से सतत निगरानी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही इन सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त रूप से छापामार कार्यवाही करते हुए मादक पदार्थों के अवैध धारण, विक्रय और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जानकारी दी गई कि आगामी विधानसभा निर्वाचन की तिथि को मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से छत्तीसगढ़ राज्य की समस्त मदिरा दुकानों, बारों, आसवनियो, बॉटलिंग यूनिट्स, देशी मदिरा के वेयरहाउस और विदेशी मदिरा गोदामों को बंद किया जावेगा। साथ ही साथ सीमावर्ती नार्दन डिवीजन उड़ीसा में सम्मिलित जिला झारसुगुड़ा की 3, बरगढ़ की 20, सुंदरगढ़ की 7 और नुआपाड़ा की 5 मदिरा दुकानें भी इस अवधि में बंद रहेंगी। दीपावली पर्व समीप होने के कारण इस हेतु

अधिक चौकसी रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, झारसुगुड़ा, बरगढ़, सुंदरगढ़ और नुआपाड़ा जिलों के आबकारी विभाग के अधिकारी सम्मिलित थे।

आबकारी विभाग द्वारा सतत कार्यवाही जारी

महासमुंद 09 नवंबर (आरएनएस)। कलेक्टर प्रभात मलिक के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी मोहित जायसवाल के मार्गदर्शन में बुधवार को संयुक्त आबकारी टीम जिला महासमुंद द्वारा महासमुंद शहर वृत्त एवं आबकारी वृत्त सांकरा अंतर्गत की गई कार्यवाही में 01-01 प्रकरण दर्ज किया गया। जिसमें महासमुंद शहर वृत्त अंतर्गत तुलसीदास मानिकपुरी, ग्राम गंजपारा वार्ड नंबर 19, महासमुंद से 8 स्टरेन बीयर मात्रा 5.200 लीटर, 4 पाव देशी मदिरा मसाला मात्रा 0.720 लीटर, 6 पाव जम्मू स्पेशल व्हिस्की 1.08 लीटर मदिरा कुल मात्रा 7.00 बल्क लीटर छत्तीसगढ़ राज्य निर्मित मदिरा जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसी प्रकार आबकारी वृत्त सांकरा के अंतर्गत की गई कार्यवाही में रामचरण पटेल, ग्राम राजाकटेल, थाना -सांकरा से एक 15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में 09 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब बाजार मूल्य 1800 रुपए एवं 03 प्लास्टिक ड्रम में कुल 300 किलो महुआ लहान बाजार मूल्य 15000 रुपए जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध प्रकरण 34(1)(क)(च), 34(2) एवं 59(क) के तहत कार्यवाही की गई।

कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी निधीश कोष्ठी एवं उत्तम बुद्ध भारद्वाज के मार्गदर्शन एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती सविता रानी मेश्राम एवं आबकारी उप निरीक्षक अनिल कुमार झारिया के नेतृत्व में की गई। कार्यवाही के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश कुमार वर्मा, हृदय कुमार तिरपुड़े, विकास बढेन्द्र का विशेष योगदान रहा। इस दौरान आबकारी मुख्य आरक्षक माधव राव, कुंजलाल ध्रुव तथा सिक्युरिटी गार्ड सचिन तिलक, वाहन चालक गांधी राम ठाकुर एवं समस्त आबकारी स्टाफ उपस्थित थे।

महिला मतदाता इसे नई उम्मीद की रोशनी के रूप में देख रही है: प्रितपाल

दुर्ग। सहकारीता नेता एवं दुर्ग ग्रामीण विधानसभा भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर के चुनाव संचालक प्रितपाल बेलचंदन ने कहा कि महतारी वंदन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई ऐसी योजना है जिसका किसी ने पहले कल्पना भी नहीं की थी। महतारी वंदन योजना के तहत हर महिलाओं का ध्यान रखा जाएगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महिला मतदाता इसे नई उम्मीद की रोशनी के रूप में देख रही है। श्री बेलचंदन ने एक बयान में कहा कि ऋण माफी से किसानों को लाभ होता है, मगर महतारी वंदन योजना से देश की एक-एक महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर के जरिए पैसा महिलाओं के खाते में सीधे आएगा । श्री बेलचंदन ने कहा कि इस बार भाजपा ने घोषणा किया है कि किसानों को 2 साल का बकाया बोनस एकसाथ दिया जाएगा। साथ ही ?3100 प्रति क्विंटल के दर पर धान खरीदी करने के पश्चात नगद पैसा तुरंत उनके हाथों में दिया जाएगा। किसानों को पैसे के लिए बैंकों का भी

चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और कई दिन इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। श्री बेलचंदन का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया महतारी वंदन योजना महिलाओं के हित का पूरा ध्यान रखेगी वहीं नई घोषणा के मुताबिक किसानों के हाथों में सीधे नगद पैसा आएगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने पहले महिला आरक्षण, फिर महतारी वंदन योजना की घोषणा कर महिलाओ को पूरा सम्मान दिया है। वही आधी आबादी को इस चुनाव में भाजपा ने अपनी ओर साध लिए है।

माइक्रो ऑब्जर्वर, पुलिसकर्मी एवं वाहन चालक भी डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान

कोरबा। मतदान दल में शामिल माइक्रो ऑब्जर्वर, पुलिस कर्मी एवं वाहन चालकों के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की व्यवस्था प्रशिक्षण स्थल में की गई है। वे 11 और 14 नवंबर को शासकीय ईव्हीपीजी कॉलेज कोरबा, शासकीय मुकुटधर पाण्डेय कॉलेज कटघोरा के प्रशिक्षण स्थल में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। अपर कलेक्टर ने बताया कि प्रशिक्षण स्थल में विधानसभा क्षेत्र रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली-तानाखार के अभ्यर्थियों तथा राजनीतिक दलों के अध्यक्ष व प्रतिनिधि भी अपनी उपस्थिति दे सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो कि कोरबा जिले के निवासी हैं और कोरबा जिले से बाहर कार्यरत् हैं तथा जिनकी मतदान कार्यों में ड्यूटी लगाई गई है।

नक्सल इलाकों में अभी भी फंसे हैं कई मतदान दल, पोलिंग पार्टियों को वापस लाना चुनौती

बीजापुर। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान भले ही संपन्न हो गया है, लेकिन सुरक्षा बल की चिंता अभी समाप्त नहीं हुई है. कई मतदान दल नक्सल प्रभावित इलाकों में अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने फोर्स जुगत लगा रही है.

बीजापुर एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने कहा, छोटी-बड़ी घटनाओं के बीच बीजापुर में मतदान सम्पन्न हुआ. अब पोलिंग पार्टियों को वापस लाना चुनौती है. घात लगाए माओवादियों से निपटने के साथ ही सभी कर्मचारियों को सुरक्षित मुख्यालय तक लाना पहली प्राथमिकता है.

बता दें कि 7 नवंबर को 20 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें बस्तर की 12 सीटों भी शामिल हैं. मतदान के दौरान नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, जिसे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया. कई जगहों पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई. जवानों की जवाबी कार्रवाई में नक्सली भाग निकले. इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है.

मंगलवार को दोपहर विधानसभा चुनाव के दौरान सर्चिंग पर निकले जवानों और नक्सलियों के बीच गंगालूर मार्ग पर मुठभेड़

हुई थी. जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली उल्टे पैर भागने को मजबूर हुए थे. यह घटना जवानों के ड्रोन कैमरे में कैद हुई है, जिसमें नक्सली घायल साथियों को कंधे में ढो कर ले जाते दिख रहे हैं.

वही बीजापुर जिले में दिनभर सर्चिंग के दौरान जवानों ने कुल 13 आईईडी बरामद किए हैं. मतदान के दौरान मतदान दल और जवानों को नुकसान पहुंचाने नक्सलियों ने अलग-अलग इलाके में आईईडी प्लांट किए थे. मौके पर बीडीएस की टीम ने बरामद आईडी को निष्क्रिय किया.

प्रेक्षक और पुलिस आब्जर्वर ने किया मतदान केंद्र, थाने का निरीक्षण

कोरबा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु कोरबा और रामपुर के लिए नियुक्त प्रेक्षक प्रियतु मंडल और पुलिस आब्जर्वर सी.वेंकटा सुब्बा रेड्डी ने ग्राम गोढ़ी में प्राथमिक शाला भवन मतदान केंद्र क्रमांक 83-84, ग्राम करमंदी में मतदान केंद्र क्रमांक 82, नोनबिर्रा में मतदान केंद्र 250-251, प्राथमिक शाला कोटमेर में मतदान केंद्र क्रमांक 117, स्वामी आत्मानंद कन्या अंग्रेजी माध्यम विद्यालय करतला के मतदान केंद्र क्रमांक 115, डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल बड़मार के मतदान केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने थाना करतला, आंगनबाड़ी केंद्र कोटमेर, नोनबिर्रा का भी अवलोकन किया। उन्होंने मतदान केन्द्रों में मतदाताओं की जानकारी हेतु किए गये दीवाल लेखन, दिव्यांग मतदाताओं हेतु बनाये गये रैम्प तथा मतदान केन्द्रों में उपलब्ध अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया और मतदान केन्द्रों में आवश्यकतानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान संबंधित बूथ लेबल अधिकारी उपस्थित थे।

20 साल में तिगुना हुआ चुनाव खर्च, क्यों बढ़ी खर्च सीमा ?

बिलासपुर। चुनाव खर्च में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण महंगाई को माना जा रहा है। 20 साल में तीन गुना महंगाई बढ़ी है और यही कारण है कि प्रत्याशियों का चुनावी खर्च बढ़ चुका है। आयोग भी निर्धारित खर्चा बढ़ा रहा है। चुनाव में प्रत्याशियों को ज्यादा प्रचार प्रसार करने का मौका मिलता है। आयोग की मंशा है कि चुनाव प्रचार और प्रत्याशी बिना किसी परेशानी के चुनाव संपन्न करा सके।

दो दशक पहले एक प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव के दौरान कम खर्च करने होते थे लेकिन यह सीमा लगातार बढ़ रहा है। अब ये आंकड़ा 40 लाख रुपए तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद 2003 में पहला चुनाव हुआ था। तब प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 14 लाख रुपए थी। बीते दो दशकों में यह सीमा तीन गुना बढ़ाई गई है। चुनाव में बेतहाशा खर्च को रोकने के लिए आयोग हिसाब किताब रख रहा है।अत्यधिक खर्च होने पर चुनाव खतरे में पड़ जाता है। लेकिन आयोग खुद ही खर्चों में बढ़ोतरी कर रहा है।

राजनीति के जानकारी हबीब खान का कहना है कि चुनाव में खर्च का निर्धारण बहुत जरूरी होता है। हर व्यक्ति चुनाव लड़

सके इसके लिए इसका निर्धारण करना अति आवश्यक है ।यदि ऐसा ना होगा तो आर्थिक रूप से सामान्य व्यक्ति इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा नहीं ले पाएगा। आयोग चुनाव खर्च बाजार की कीमतों के मुताबिक तय करता है। आयोग बाजार में बढ़ती महंगाई के साथ ही सामानों की कीमतों और विज्ञापन में निर्धारित अमाउंट के मुताबिक करता है।

निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान उपयोग होने वाले सामानों और खाद्य सामग्री सहित सभी मशीनरियों के बाजार मूल्य के मुताबिक रेट तय करती है। प्रत्याशियों को इसी के मुताबिक खर्च करने की छूट दी जाती है। दो दशक में बाजार में महंगाई बढ़ी हैं। यही कारण है कि 20 साल में चुनाव खर्च 14 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए तक पहुंच गया है।

नारायणपुर में एक्सीडेंटल फायरिंग से एक डीआरजी जवान घायल

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर में गुरुवार को जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) का एक जवान दुर्घटनावश घायल हो गया। बताया जा रहा है डीआरजी की सर्चिंग अभियान के दौरान आकस्मिक गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। घायल जवान की उंगलियों में चोट आई है। जवान को फौरन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ओरछा लाकर उपचार कराया गया है। जवान की स्थिति खतरे से बाहर है। यह पूरा मामला ओरछा थाना क्षेत्र का है।

नारायणपुर एएसपी हेमसागर सिदार ने बताया, आज थाना ओरछा से डीआरजी की टीम क्षेत्र में सर्चिंग अभियान के लिए निकली थी। तभी टीम के एक जवान के हथियार से एक्सीडेंटल फायरिंग हो गई। जिससे उसकी उंगलियों में चोट आई है। जवान को तत्काल पीएचसी ओरछा ले जाया गया और प्राथमिक उपचार कराया गया। जवान की स्थिति सामान्य है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को प्रभावित करने के लिए नक्सलियों ने कई प्रयास किये, लेकिन नक्सलियों की हर साजिश को सुरक्षाबलों ने सतर्कता और कुशल रणनीतियों से नाकाम कर दिया है। 7 नवंबर को पहले चरण के मतदान के दौरान बीजापुर, सुकमा, कांकेर, दंतेवाड़ा समेत कई जगहों पर सुरक्षाबलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी। इसके साथ ही कुछ जगहों से आईईडी भी बरामद की गई थी। इस दौरान कांकेर में आईईडी की चपेट में आने से बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था। इसके अलावा कुछ छुटपुट घटनाओं के अलावा कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई थी।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

106 साल के हबीबुद्दीन अंसारी करेंगे घर बैठे मतदान

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में 80 प्लस बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए पोलिंग टीम घर पहुंच कर मतदान करवा रही है। इस बीच बलरामपुर में भी गुरुवार को मतदान दल जिले के शंकरगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत चलगली पहुंचेगी। यहां 106 साल के बुजुर्ग मतदाता हबीबुद्दीन अंसारी घर बैठे मतदान करेंगे। हबीबुद्दीन अंसारी ने बताया कि, मैं घर बैठे इस बार पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करूंगा। इसके लिए मतदान दल मतदान कराने के लिए गुरुवार को घर आएगी। बलरामपुर जिले में दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होना है, उसके पहले जो बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता मतदान केन्द्र नहीं पहुंच पाएंगे। उनके लिए निर्वाचन आयोग ने घर पर ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की व्यवस्था की है। मेरी लोगों से अपील है कि वो वोट जरूर करें। उन्होंने कहा वोट देना जरूरी है। सभी मतदाताओं को अपना बहुमूल्य वोट देना बहुत जरूरी है। मतदान के दिन घर पर नहीं रहना है। सभी को मतदान केन्द्र जाकर वोट देना चाहिए।

गिरदावरी में घटाया गया धान का रकबा सुधारा जाए : कंवर

कोरबा। जिले के कद्दावर आदिवासी नेता और रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक ननकीराम कंवर ने गिरदावरी के नाम पर किसानों के धान का रकबा घटाने की ओर कलेक्टर कोरबा का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गिरदावरी रिकार्ड में सुधार करने की मांग कलेक्टर से की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान कृषि वर्ष में सभी किसानों के धान की फसल का रकबा गिरदावरी की आड़ में कम कर दिया गया है। किसानों के बार बार अनुरोध करने के बाद भी पटवारियों ने गिरदावरी रिकार्ड में सुधार नहीं किया है। राजस्व विभाग के उच्च अधिकारी भी किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। विधायक श्री कंवर ने कलेक्टर कोरबा से किसानों की समस्या को संज्ञान में लेकर त्वरित निराकरण की मांग की है। भाजपा विधायक कंवर ने यह भी कहा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर सभी किसानों को उनके धान उत्पादन के वास्तविक रकबा के आधार पर समर्थन मूल्य से धान की खरीदी की जाएगी। पटवारियों द्वारा की गई गिरदावरी को धान खरीदी का आधार नहीं माना जाएगा।

अब नेशनल लोक अदालत का आयोजन 16 दिसम्बर को

कोरबा। डी. एल. कटकवार, जिला एवं सत्रा न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरण दांडिक, सिविल, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं राजस्व न्यायालयों के राजीनामा योग्य प्रकरणों को शामिल करते हुये नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में समझौते के माध्यम से निराकरण किये जाने हेतु जिला अधिवक्ता संघ कोरबा के पदाधिकारीगणों की बैठक ली गई। पूर्व में नालसा के द्वारा उक्त नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 09 दिसम्बर 2023 को किया जाना प्रस्तावित था परंतु अब उक्त तिथि को परिवर्तित करते हुए वर्ष 2023 का अंतिम नेशनल लोक अदालत दिनांक 16 दिसम्बर को आयोजित किया जाएगा। न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है।

पुलिस ने गुड़ाखू से भरे 3 कंटेनर किए जब्त

पेंड्रा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एफएसटी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें गुड़ाखू से भरे तीन कंटेनर को जब्त किया है। इन जब्त किए गए गुड़ाखों की कुल कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पूरा मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का है जहां एसएसटी टीम के द्वारा छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र कबीर चबूतरा में चेकिंग पॉइंट लगाकर चुनाव के मद्देनजर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान दिल्ली से बेंगलुरु के लिए निकले कंटेनर कबीर चबूतरा के पास पहुंचा। जहां वाहन की चेकिंग करने पर पुलिस ने तीनों वाहनों में गुड़ाखू बरामद किया मामले में दस्तावेज की मांग की गई तो दस्तावेज में ई ई परमिट न होने के कारण एफएसटी टीम ने तीनों कंटेनर को जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई हेतु जीएसटी के अधिकारियों को सौंप दिया है।

ट्रेलर में ब्लास्ट होते ही लगी आग, चालक ने बचाई जान

कोरबा। कोरबा के उरगा हाटी राजमार्ग में कोटमेर के समीप चलती ट्रेलर में भीषण आग लग गई। ट्रेलर के चालक ने किसी तरह छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। जब तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाते ट्रेलर जलकर खाक हो चुका था। इस वजह से मुख्य मार्ग पर करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा। जिसे खुलवाने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि मूलतः बिहार निवासी महेंद्र मेहता वाहन चालक का काम करता है। वह शाह कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रेलर क्रमांक सीजी 13 एडी 83 60 को लेकर कोरबा की ओर आ रहा था। वह करतला थाना अंतर्गत ग्राम कोटमेर के समीप पहुंचा था। इसी दौरान उसे इंजन से ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। वह कुछ समझ पाता, इससे पहले धुएं के साथ आग की लपटें निकलने लगी। इस आग ने देखते ही देखते पूरे केबिन को चपेट में ले लिया। किसी तरह चालक ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। मुख्य मार्ग पर ट्रेलर धूं-धूं कर जलने लगा। जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लगनी शुरू हो गई।

धान खरीदी हेतु विधिवत पूजन कर छुरीकला में धान खरीदी का शुभारंभ

कोरबा। खरीफविपणन वर्ष 2023-24 अंतर्गत जिले में 01 नवंबर 2023 से धान खरीदी कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने आज कटघोरा विकासखण्ड के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित केंद्र छुरीकला में धान खरीदी हेतु धान एवं कांटा बाट का विधिवत पूजन कर केंद्र में धान खरीदी का शुभारंभ किया। धान उपार्जन केंद्र छुरीकला में कृषक रामानुज साहू पिता सुकालूरामू द्वारा विगत दिवस 20 क्विंटल धान विक्रय हेतु टोकन कटवाया गया था, जिसे आज उनके द्वारा विक्रय हेतु उपार्जन केंद्र छुरीकला लाया गया। कलेक्टर सौरभ कुमार ने कृषक रामानुज साहू को शुभकामनाएं देते हुए समिति प्रबंधक को धान खरीदी कार्य सुचारू रूप से संचालित कराने हेतु केंद्र में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने एवं सभी समितियों में गुणवत्ता युक्त धान खरीदी करने के लिए कहा। कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की सतत् निगरानी रखने

एवं कोचियों एवं बिचैलियों से अवैध धान की खरीदी-बिक्री पर मंडी अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया।

इस दौरान खाद्य अधिकारी जितेन्द्र सिंह ने कलेक्टर सौरभ कुमार जानकारी देते हुए बताया कि उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की सतत् निगरानी हेतु केंद्रवार निगरानी समिति का गठन किया गया है। साथ ही इस गठित निगरानी समिति में पटवारी/राजस्व निरीक्षकों को नामांकित प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है तथा धान खरीदी की निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को नोडल नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में अवैध धान के विक्रय पर रोक लगाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में राजस्व विभाग, खाद्य व मण्डी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम का गठन कर अनुविभाग स्तरीय जांच दल का निर्मित किया गया। इस अवसर पर जिला खाद्य अधिकारी जितेन्द्र सिंह, उप पंजीयक सहकारिता श्रीमती पूर्णिमा सिंह, डीएमओ श्रीमती जाह्नवी जिलहरे, एस. के. जोशी सहित अन्य अधिकारी एवं समिति के कर्मचारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन 01 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2023 तक जिले के 41 सहकारी समितियो के 65 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान उपार्जन किया जाना है। समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु 31 अक्टूबर 2023 की स्थिति में कुल 52,390 किसानों के 70,592.88 हेक्टेयर रकबा का पंजीयन किया गया है। जिस हेतु सभी 65 धान उपार्जन केन्द्रों में धान की खरीदी हेतु मूलभूत सुविधाएं एवं अन्य आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।

सुचारू रूप से धान खरीदी कार्य हेतु धान उपार्जन केंद्र के कर्मचारियों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों को प्रशिक्षण दिया गया है। सभी केंद्रों में धान खरीदी कार्य हेतु नया जूट बारदाना एवं पुराना बारदाना आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जा रही है। कोरबा जिले में 08 नवंबर 2023 की स्थिति में 03 किसानों से कुल 86 क्विंटल धान की खरीदी की गई है।

80 प्लस बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने घर पर किया मतदान

कोरबा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार के निर्देशन में जिले में विधानसभा निर्वाचन की व्यापक तैयारियां है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं (पीडब्ल्यूडी) को घर बैठे मतदान की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। इसी कड़ी में आज रामपुर और पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र के 80 वर्ष से अधिक आयु तथा दिव्यांग मतदाताओं में मतदान दलों की उपस्थिति में घर पर भी मतदान करके लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता दी। 10 नवंबर को विधानसभा कटघोरा तथा कोरबा क्षेत्र में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होम वोटिंग कराई जाएगी। इसके लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। होम वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी व अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। होम वोटिंग से पूर्व मतदान दल के अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान कराने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि जिले में प्रारूप 12 (घ) में आवेदन करने वाले अनुपस्थित श्रेणी के अंतर्गत मतदाताओं ने सहमति दी है। गठित दल द्वारा चिन्हित मतदाताओं के घर पहुंचकर पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मतदान की कार्यवाही संपन्न कराएंगे।

संक्षिप्त समाचार

अवैध गुटखा फैक्ट्री का हुआ खुलासा, टीम पहुंची छापा मारने तो माल गायब

रायपुर। राजधानी में गुटखा का अवैध कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। इसी तरह का मामला भनपुरी के इंडस्ट्रिल एरिया का सामने आया है। उरला में तुलसी पटेल के गोदाम में 3 नामी ब्रांड का नकली गुटखा बनाने की शिकायत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को हुई थी। इससे पहले की टीम पहुंचती, शातिर तस्करों ने करोड़ों का गुटखा और बनाने की मशीन गायब कर दी। खाद्य विभाग गुटखा माफ्मिाओं के नए ठिकाने को तलाश रही है। बता दें कि उरला इलाके में तुलसी पटेल का बड़ा गोदाम है। यहां मध्यप्रदेश छिंदवाड़ा के 15 मजदूरों को रखकर तंबाखू, पाउडर और कैमिकल मिलवाया जाता था। इसके बाद इसे ब्रांडेड गुटखा के पैकेट में भरकर प्रदेश भर में सप्लाई किया जा रहा था। गुटखा बनाने का काम देर रात चलता था। दिन में लेबर सोते थे, जिससे आसपास के लोगों को इस अवैध फैक्ट्री की भनक न लग पाए। मामला बीते सप्ताह का है। यहां पर एक अवैध गुटखा फैक्ट्री होने की जानकारी खाद्य विभाग के आला अधिकारियों को देर रात हुई थी। दिन में जब खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो पूरा परिसर खाली कर दिया गया था। शिकायतकर्ता ने विभाग के कंट्रोलर को मौके का फेटो वीडियो उपलब्ध कराया था, इसके बाद टीम छापा मारने पहुंची थी।

रायपुर में साफसफाई की व्यवस्था हुई खराब, कचरे से लोगों का हुआ बुरा हाल

रायपुर। धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा ये तीनों त्योहार करीब हैं। त्योहार के मद्देनजर लोग अपने घरों की साफ-सफाई में जुट गए हैं। रायपुर नगर निगम के मुताबिक जितना कचरा पहले एक दिन में उठता था उससे दोगुना ज्यादा कचरा अब एक दिन में उठ रहा है। निगम के आंकड़ों की मानें तो 10 दिनों से कचरे की मात्रा बढ़कर 540 टन तक पहुंच गई है। रायपुर नगर निगम को अब इन कचरों को उठाने और निपटाने में न सिर्फ कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही बल्कि मैन पावर भी ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। नगर निगम के आयुक्त विनोद पांडे के मुताबिक सभी वार्डों में सफाई अभियान चल रहा है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम भी जारी है। डोर टू डोर कचरा उठाने का काम निगम ने रामकी कंपनी को दिया है। कंपनी की ओर से फ्लिहाल 242 वाहनों के जरिए कूड़ा उठाया जा रहा है। लेकिन त्योहार के चलते लोग घरों की सफाई ज्यादा कर रहे हैं जिससे कचरा दोगुना उठाना पड़ रहा है। पहले जहां एक गाड़ी 2 से 3 ट्रिप लगाती थी वहीं अब 5 से 6 ट्रिप एक गाड़ी को लगानी पड़ रही है। नगर निगम तो ये दावा कर रही है कि वो कचरा समय पर और पूरा उठा रही है, लेकिन शहर के लोगों का कहना है कि निगम की गाड़ी एक बार कचरा लेकर निकल जाती है तो दूसरी बार लौट कर नहीं आती। कचरे की गाड़ी दोबारा नहीं आने पर लोग सड़क किनारे कचरा फेंक देते हैं जिससे कूड़े का अंबार चौक चौराहों पर लग जाता है। कूड़े के ये ढेर हादसों को भी दावत देते हैं, मवेशियों की जान के भी दुश्मन बनते है।

खड़ी ट्रेलर से टकराई बस, पीड़ित ने स्वस्थ होने के बाद दर्ज कराई शिकायत

रायपुर। बस किराए पर लेकर अमरकंटक घूमने जा रहे ग्रामीणों से भरी बस के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए रानीगांव के पास खड़ी ट्रेलर को ठोंक दिया था। घटना में घायल ने उप के बाद स्वस्थ होने के बाद रतनपुर थाने पहुंच शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार ग्राम भरेवा मुंगेली निवासी अशोक कुमार पिता शिव प्रसाद सिंगरौल (36) ने रतनपुर थाने पहुंच कर बस चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि 22 अगस्त को अमरकंटक जाने के लिए गांव के लोगो ने बस किराए पर की थी। बस क्रमांक सीजी 10 बीड़ी 5958 में गांव के 45 लोग सवार होकर अमरकंटक के लिए निकले थे। बस रात में 3 बजे के आस-पास रानीगांव के पास एनएच 130 में पहुंची थी। इस दौरान बस चालक ने सड़क किनारे खड़ी हाइवा के पीछे ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। स्वस्थ होने पर पीड़ित ने बस क्रमांक सीजी 10 बीडी 5958 के चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है।

नरेंद्र मोदी की गारंटी है, भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे : रविशंकर

■ भूपेश बघेल अपने सलाहकार के जरिये भाजपा को नोटिस भेज रहे है तो उसका माकूल जवाब देने भाजपा सक्षम है

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज यहां भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद पूरे छत्तीसगढ़ का माहौल यह स्पष्ट बता रहा है कि भूपेश बघेल की सरकार जा रही है और भाजपा की सरकार आ रही है। यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि दूसरे चरण के मतदान में भी भाजपा को ऐतिहासिक समर्थन मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता का कांग्रेस सरकार से भरोसा उठ चुका है। छत्तीसगढ़ की जनता का भूपेश बघेल से भरोसा उठ चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही सरल सहज स्वभाव की है और इस तरह का भ्रष्टाचार और इस तरह की नेतागिरी और इस तरह के शासन की छवि उन्हें पसंद नहीं।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं की मजबूती के लिए मोदी की गारंटी है कि यहां की वैवाहित महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को, बहुओं को 1000 रुपए महीना मिलेगा तो मिलेगा।और जिनके घरों में 2 है उन्हें 2000 रु प्रतिमाह और 3 होने पर 3000 रु प्रतिमाह मिलेगा। हमने मध्यप्रदेश में यह करके दिखा दिया है। यहां भी देंगे और 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी देंगे।

उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि भूपेश बाबू ऐप से बहुत प्रेम करते हैं। मुझे यह नहीं मालूम था कि जब मैं आपसे दूसरी बार मिलूंगा तो महादेव एप की कहानी इतनी बड़ी हो जाएगी। महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। भूपेश बघेल झूठ क्यों बोल रहे हैं कार्रवाई करना और कार्रवाई करने का दिखावा दिखाना, यह दोनों अलग-अलग बात है। भूपेश बघेल कहते है कि महादेव एप बंद करने चिट्ठी लिखी थी वे बताएं कि कब कौन सी चिट्ठी लिखी। भूपेश बघेल ने कोई चिट्ठी नही लिखी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्पष्ट लिखा है कि भूपेश बघेल ने ऐसी कोई चिट्ठी नहीं भेजी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इस मामले में पूरी ईमानदारी के साथ क्या काम किया यह बताया जाए। मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन में पुलिस की मिलीभगत सामने आयी है और इनके चेहरे भी बेनकाब हुए है।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस द्वारा ईडी पर केन्द्र सरकार के दबाव में काम करने के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के जितने करीबी ईडी की पड़ताल के बाद जेल गए है वे वहीं हैं कि नहीं? भूपेश बघेल यदि अपने सलाहकार के जरिये भाजपा को नोटिस भेज रहे है तो उसका माकूल जवाब देने भाजपा सक्षम है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं कि नहीं, संजय सिंह जेल में हैं कि नहीं, संजय सिंह उनके पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता हैं आम आदमी पार्टी के इन लोगों का कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट से हुआ कि नहीं, बंगाल में एक मंत्री जी के यहां से 70 करोड़ कैश मिला था कि नहीं, याद है कि नहीं, दूसरे जो जेल गए हैं उनके पूरा कैश मिल रहा है कि नहीं तो आप कभी सच्चाई पर बात नहीं करते। लालू प्रसाद जेल गए कि नहीं, कभी तथ्य पर बात नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार करेंगे तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि भ्रष्ट लोगों को नहीं छोड़ेंगे। यदि छत्तीसगढ़ में महादेव एप के मामले में डेढ़ साल से आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आपने केन्द्र सरकार को पत्र क्यों नहीं लिखा।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं देश का लगभग 8 साल तक आईटी मंत्री रहा हूं। भूपेश बाबू या तो आप महादेव एप बैन की इच्छा नहीं रखते थे या आपको एडवाइस नहीं मिली तो जो भी कहा जाए अगर 500 करोड रुपए का ट्रांजैक्शन है तो क्या होगा, यह बात हम जानना चाहते हैं। उन्होंने महिलाओं पर अपराध के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं पूरे घमंडियां गठबंधन का रिकॉर्ड क्या है। नितीश बाबू ने महिलाओं को लेकर क्या बोला है, इतनी शर्मिंदगी में बोल नहीं सकता हूं और क्या कहा कि मेरी बात से ठेस लगी है तो मैं माफी मांगता हूं। यह कहने में भी उन्हें रात भर का समय लग गया। उन्होंने दबाव में खेद व्यक्त किया है।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तीन तलाक के समर्थन में कौन था? शाहबानो का विरोध किसने किया था? छत्तीसगढ़ में तो मेनिफेस्टो को लेकर चर्चा बहुत कुछ है मेनिफेस्टो को लेकर वादे क्या है पहले उन्हीं के वादे की बात शुरू करते हैं क्योंकि आपका रिकॉर्ड कैसा है? इस प्रकार से आप बेनिफिशियल लेकर आते हैं तो आपके पुराने मेनिफेस्टो को पूरा करने का क्या रिकॉर्ड है? कहा था शराबबंदी करेंगे और शराबबंदी तो छोड़ दीजिए शराब की कमाई में सरकार की जगह गैर सरकारी भी आ गए। जिनके ऊपर किसी का हाथ था। कहा गया था कि हम गैस सिलेंडर देंगे न तो चार गैस सिलेंडर मिले और न बेरोजगारी भत्ता मिला। युवाओं को पांच साल में 15000 करोड़ का वादा किया गया था, नही मिला।पूर्व केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोरोना काल में मुफ्त वैक्सीन की जानकारी देश की जनता को मोबाइल से मिली थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि देश में अगर 120 करोड़ मोबाइल फोन है 85 करोड़ स्मार्टफोन है। वैक्सीन की जानकारी मोबाइल पर पहुंची। कहा था किसानों को 6000 रुपए मिलेंगे तो मिले या नहीं, मैं सड़क पानी बिजली की बुनियादी बात करता हूं। यह मिला कि नहीं मिला। 80 करोड़ गरीब लोगों को खाना खिलाया कि नहीं खिलाया। यह होता है कमिटमेंट डिलीवरी। जब मोदी जी कुछ कहते हैं तो पक्की गारंटी होता है।

भाजपा सांसद मोहन मंडावी का दावा, कहा-

प्रथम चरण में 20 में से 16 से 17 सीटें जीतेगी भाजपा

बालोद। 7 तारीख को हुए प्रथम चरण के मतदान के बाद कांग्रेस ने दावा किया था कि वो 15 से 17 सीटें जीतेगी। कांग्रेस के दावे के बाद कांकेर से बीजेपी सांसद मोहन मंडावी ने दावा किया है कि बीजेपी पहले चरण की 20 सीटों में से 16 से 17 सीटें जीत रही है। मोहन मंडावी का कहना है कि पहले चरण में जनता का जो रुझान सामने आया वो बीजेपी के लिए उत्साहजनक है। वोटरों ने पहले ही चरण में ये साबित कर दिया कि जनता को बीजेपी पसंद है।

कांकेर से बीजेपी सांसद मोहन मंडावी का दावा है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले जो भी वादे जनता से किए थे वो सारे वादे अधूरे हैं। जनता ने इस बार अधूरे वादों पर वोट नहीं दिया। कांग्रेस ने जनता के सामने 36 वादे किए थे लेकिन 36 में से एक भी वादे कांग्रेस ने पूरे नहीं किए, अब जनता उन वादों का हिसाब मांग रही है। मंडावी ने दावा किया कि जनता परिवर्तन के लिए वोट देगी। मंडावी ने कहा कि जहां तक बीजेपी के विरोध की बात है कहीं भी बीजेपी का विरोध जनता के बीच नहीं है। मोहन मंडावी कांकेर संसदीय सीट से सांसद है। मोहन मंडावी के दावों में कितना दम है ये चुनाव के नतीजों से साबित हो जाएगा। बस्तर और दुर्ग संभाग की सीटों के बाद अब बाकी बची सीटों पर 17 तारीख को मतदान होना है। दोनों ही दलों के दिग्गज प्रत्याशी मैदान में मेहनत कर रहे हैं। जीत किसके पक्ष में जाएगा ये कहना मुश्किल है पर हां दोनों ही दलों ने दावों में जरूर अपने आप को अभी से विजेता घोषित कर दिया है।

भूपेश बघेल दिखते सीधे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया : जयराम

■ हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का छत्तीसगढ़ सीएम पर हमला

रायपुर। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। जयराम ठाकुर ने बीजेपी के एकात्म परिसर में प्रेसवार्ता की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बघेल ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं पार कर दी है। दिखने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी सीधे-साधे और चिकने चुपड़े दिखते हैं। हालांकि हैं नहीं। मध्य प्रदेश के देवास में पिछले दिनों प्रियंका गांधी आई थी, सभा में उन्होंने कहा था कि ऐसे नेता और जनप्रतिनिधि जो चुनाव के समय घोषणा करते हैं और उन घोषणाओं को पूरा नहीं करते हैं, ऐसे नेताओं को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जनघोषणा पत्र में किये गए वादे आज भी आधे अधूरे हैं। कई घोषणाएं पूरी भी नहीं हो पाई है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस ने 10 घोषणाएं की। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बन गई। लेकिन सरकार बने आज 11 महीने बीत गए हैं लेकिन चुनाव के पहले कांग्रेस सरकार ने जो गारंटी किए थे। उसमें 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने कैबिनेट की पहली बैठक में जनवरी के महीने में 1500 रुपए देने की बात कही थी, जो आज तक पूरी नहीं हो सकी। हिमाचल प्रदेश के किसी भी महिला के खाते में एक रुपया भी नहीं आया है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कई आरोप भी लगाए। हालांकि अब तक कांग्रेस ने जयराम ठाकुर के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की है।

छत्तीसगढ़ में भी दलित आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा : मायावती

बिलासपुर। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के चुनावी प्रचार के बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमों मायावती भी आज पार्टी उम्मीदवार के प्रचार के लिए बिलासपुर पहुंची हुई है। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा पर जोरदार प्रहार किया। मायावती ने दोनों ही दलों पर आदिवासी, दलितों की अनदेखी के साथ उनपर अन्याय करने के आरोप लगाएं।

मायावती ने कहा कि दमदारी और पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लंबे समय तक सत्ता में रखने वाले लोग यही दलित आदिवासी हैं। आजादी के बाद से कांग्रेस ने दलित आदिवासियों को लेकर ध्यान नहीं दिया इसीलिए बसपा जैसी पार्टी बनी। कांग्रेस भाजपा सहित अन्य विरोधी दलों ने आरक्षण का कोटा अब तक पूरा नहीं किया। महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण में भी एसटी एससी वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं।

मायावती ने फिर दोहराया कि छग में भी दलित आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। आदिवासियों को जबरन नक्सली बताकर शोषण किया जा रहा। यहाँ दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की भी हालत ठीक नहीं है। अपर क्लास गरीबों की हालत भी दयनीय बनी हुई है। केंद्र के भाजपा सरकार के नीतियों के कारण किसानों की स्थिति खराब है। गलत नीतियों के कारण देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है। मायावती ने दावा किया कि देश में गिने चुने धन्नासेठों का केवल विकास हो रहा। देश में हर स्तर पर भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है। छग में भी बड़ा भ्रष्टाचार है। कांग्रेस भाजपा दोनों दलों ने छग के लिए कुछ नहीं किया।

मोदी और आरएसएस संविधान बदलने की कोशिश कर रहे : खड़गे

बैकुंठपुर, कोरिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कोरिया के बैकुंठपुर में प्रचार के लिए पहुंचे। खड़गे ने कहा कि ये चुनाव देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। मोदीजी अडाणी के लिए लड़ते हैं हम गरीबों के लिए लड़ते हैं। यहीं कांग्रेस और बीजेपी में अंतर है। खड़गे ने कहा कि हमारी सोच है कि गरीब का बच्चा और और अमीर का बच्चा दोनों एक जैसी शिक्षा पाए, पर बीजेपी के नेता समाज को बांटना चाहते हैं जाति, धर्म और पैसों के आधार पर। खड़गे ने कहा कि अगर मोदी और रमन सिंह को हराना है मैदान से बाहर बिठाना है तो सभी पांच राज्यों में कांग्रेस को जिताना होगा तभी कांग्रेस का सच्चा राज आएगा।

बीजेपी चुनाव सीबीआई, ईडी और आईटी के जरिए लड़ रही है। खड़गे ने बीजेपी से सवाल पूछते हुए कहा कि छापे सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर ही क्यों पड़ते हैं, जनता ये जानना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को उनका हक देना चाहती है पर बीजेपी के लोग उस हक को छीनना चाहते हैं।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस तेजी से विकास हो रहा है, उसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। बीजेपी के राज में बस बीजेपी के नेताओं का ही विकास हो रहा है। बैकुंठपुर की सभा से मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर पीएम मोदी को जहां दूरदर्शन बताया वहीं कहां कि हमारे नेता राहुल गांधी पूरे देश में घूमते हैं आम लोगों से मिलते हैं, ये आम आदमी की कांग्रेस है।

सिद्धार्थनाथ ने मेरी मानहानि की है, बदनाम करने का षडयंत्र, माफी मांगें या मुकदमा झेलें : विनोद वर्मा

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने मेरी मानहानि की है। भाजपा के दो प्रदेश प्रवक्ता भी इसमें शामिल हैं। जानबूझकर बदनाम करने का षडयंत्र किया गया है। चेतावनी देते हुए कहा कि वे लोग माफी मांगें या मुकदमा के लिए तैयार रहें।

उन्होंने कहा कि महादेव ऐप की जांच का काम छत्तीसगढ़ पुलिस ने शुरु किया। अब तक 72 मामले दर्ज किए गए हैं और 449 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।191 लैपटॉप, 865 मोबाइल फ़ोन और डेढ़ करोड़ से अधिक की संपत्ति और 16 करोड़ रुपए बैंक खातों में जब्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में दर्ज मामलों के आधार पर ही प्रत्यावर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जांच शुरू की है। रायपुर पुलिस के साइबर सेल ने 12 अक्टूबर 2022 को गूगल को एक पत्र लिखकर कहा था कि महादेव ऐप गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है, चूंकि भारत में जुआ खेलना अपराध है। इस ऐप के माध्यम से जुआ खिलवाया जा रहा है, इस ऐप को बंद कर दिया जाए और इस ऐप को बनाने और चलाने वालों के नाम पुलिस को बताए जाएं। इस पत्र के बाद गूगल ने महादेव ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने ही जांच के बाद पाया कि महादेव ऐप के संचालक रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर हैं। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया। इसके बाद से लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कह रहे हैं कि इन अपराधियों को केंद्र सरकार गिरफ़्तार करे क्योंकि वे इस देश में नहीं रहते और छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि वे किसी अपराधी को किसी दूसरे देश से गिरफ्तार करके लाएं। महादेव ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी उन्होंने कई बार की है। उन्होंने आशंका जाहिर की थी कि ऐप पर रोक इसलिए नहीं लग रही है कि क्योंकि भाजपा के लोगों से संचालकों की सांठगांठ हो गई है।

कांग्रेस ने उठाए सवाल

ईडी ने अब तक इस मामले में जिस तरह की कार्रवाई की है उससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। एक अनजान व्यक्ति के बयान पर ईडी ने प्रेस नोट जारी कर दिया कि वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पैसे पहुंचाता था। अभी इस बात की जांच बाक़ी है कि इस बयान का सच क्या है, लेकिन ईडी ने भाजपा को चुनावी हथियार दे दिया है। ईडी ने इस बारे में अभी कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया है कि रवि उप्पल के भाई राहुल उप्पल की फ़ोटो भाजपा के जिन नेताओं से साथ दिखी है उनके बारे में वह क्या करने जा रही है। वह यह भी नहीं बता रही है कि महादेव ऐप के मालिकों में से एक सौरभ चंद्राकर की फ़ोटो जिस भाजपा नेता के साथ मिली है उसके बारे में वह क्या कर रही है। अभी यह भी जानना बचा है कि जिस कार में वह पैसा मिला, उसके मालिक के संबंध में वह क्या कार्रवाई करने जा रही है जो कथित तौर पर एक भाजपा नेता का भाई है। जिस व्यक्ति से करोड़ों की रकम बरामद हुई उसकी फ़ोटो भी भाजपा के एक बड़े नेता के साथ है, तो उनसे भी क्या पूछताछ होगी? इन सवालों के जवाब अभी नहीं मिलेंगे क्योंकि चुनाव का समय है और भाजपा के ऐम्बेडेड डिटेक्टिव्स यानी ईडी अभी अपने आकाओं के खिलाफ़ कार्रवाई तो दूर सोच तक नहीं सकती।

राजभवन में दीपावली मिलन समारोह आयोजित

रायपुर। दीपावली पर्व के अवसर पर आज राजभवन में दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन, राज्य की प्रथम महिला श्रीमती सुप्रभा हरिचंदन ने राजभवन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। राजभवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी राज्यपाल को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यपाल श्री हरिचंदन ने कहा कि दीपावली पर्व एक ऐसा पवित्र दिन जब पाप का विनाश और धर्म की विजय हुई। भगवान राम का वनवास और सीता हरण के बारे में हम सब जानते है। भगवान राम ने रावण को मारकर संसार को उसके आतंक से मुक्त किया और विजयी होकर दीपावली के दिन अयोध्या लौटे थे। यह हमारे लिए अत्यंत शुभ अवसर है। राज्यपाल ने कहा कि भगवान राम, माता सीता और महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद छत्तीसगढ और आप सभी पर बना रहे। राज्यपाल के सचिव श्री अमृत खलखो ने भी अपना संबोधन दिया और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यपाल के विधिक सलाहकार श्री आर.के. श्रीवास्तव, राज्यपाल के उप सचिव श्री दीपक कुमार अग्रवाल, राज्यपाल के परिसहाय द्वय श्री विवेक शुक्ला, श्री निशांत कुमार तथा राजभवन के सभी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

न बोलिए ऐसी बानी, जो प्रतिष्ठा पर फेर दे पानी

स्वाति

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में महिलाओं को लेकर दिये गये अपने आपत्तिजनक बयान पर चाहे माफ़ी मांग ली हो और स्वयं की निंदा कर ली हो पर सच यही है कि स्त्री अस्मिता और विधानसभा व विधान परिषद की गरिमा को जो क्षति उन्होंने पहुँचा दी है वह अपूरणीय है। मंगलवार को विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते-बोलते नीतीश बाबू अपनी भाषा, सोच और मर्यादा से नियंत्रण खो बैठे। वायरल होते उनके वीडियो को देखकर प्रथम दृष्टया तो लगा शायद वीडियो मोर्फड किया गया है क्योंकि किसी भी प्रदेश के मुखिया से सभा के पटल पर ऐसी निंदित भाषा और भाव भंगिमा की अपेक्षा तो अकल्पनीय ही है। परंतु जब पुष्ट माध्यमों से खबरें और विचार- विमर्श आने लगे तो सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। सियासी गलियारे में हाय-तौबा मचता देख नीतीश कुमार ने माफ़ी तो मांग ली है पर माफ़ी मांगते समय भी जो तेवर और भंगिमा थी वह किसी भी तरीके से स्वीकृत नहीं है। उनका माफीनामा इस तरह का है जैसे उन्होंने माफी मांग कर आपत्ति करनेवालों को चिढाया है। उनको इस बात का इल्म अभी तक नहीं है कि विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने कितनी घटिया और फूहड़ भाषा का प्रयोग किया है। भाजपा ने तो मुख्यमंत्री के मानसिक स्वास्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया है और जाँच के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात पर अड़ गई है। भाजपा ने यह आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री को डिम्नेशिया हो सकता है जिसमें वो बातें भूलने लगे हैं। साथ में उन पर अश्लीलता को एंजॉय करने का भी आरोप भाजपा ने लगाया है। सोशल मीडिया पर उनके डोप टेस्ट की भी मांग उठने लगी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्त्री शिक्षा की महत्ता और जनसंख्या नियंत्रण में उनकी भागीदारी को ऐसे समझाने की कोशिश की जिसे सुनकर उनके पीछे बैठी उनकी ही पार्टी महिला विधायक ने शर्म से अपना मुंह छिपा लिया। उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद में खड़े होकर जिस प्रकार की निहायत सड़कछाप भाषा में पति पत्नी के बीच बननेवाले शारीरिक संबंध में डालने और बाहर पानी निकालने जैसे असभ्य और सांकेतिक पोर्न शब्दावली का इस्तेमाल किया है वैसी भाषा बिहार के बदनाम भोजपुरी गायक भी अपने गीतों में इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे। नीतीश कुमार यह बताना चाह रहे थे कि विवाह के बाद शारीरिक सम्बन्ध बनाते समय पढ़ी-लिखी लड़कियां इस बात का ख्याल रखती हैं ताकि वह अनचाहे गर्भ की चिंता से मुक्त रहे। मगर इसी बात तो बिहारी अंदाज में नीतीश कुमार ने सदन में कुछ ऐसे रखा कि आज कोई भी उसको दोहरा तक नहीं सकता। इस तरीके का संवाद आने पर सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट दे देता है। मगर एक प्रदेश के सीएम ने बिना किसी एडिटिंग के निर्लज्जता से हँसते हुए इस बात को कह डाला जिसे दोहराते हुए किसी भी संतुलित इंसान की जिह्वा थरथरा जाए। नीतीश कुमार के बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस फूहड़ बयान को एक बार को स्लिप ऑफ टांग मान भी लिया जाता परंतु विधान परिषद में अपने बयान के ठीक बाद इसकी पुनरावृत्ति भी कर दी। तब इसे सोचा समझा बयान ही माना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके इस बयान की निंदा की परंतु ऐसे बयान के कुप्रभाव को क्या दोषी की निंदा कर लेने भर से या उसके माफी मांग लेने से कम किया जा सकता है? जिस देश में अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने के गलत तरीके अपनाने से हर रोज 8 महिलाओं की मृत्यु हो रही हो वहाँ ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर मसखरी करना जनता का दुर्भाग्य ही है। 25.5/1000 शिशु जन्म दर के साथ बिहार भारत का अग्रणी राज्य है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जन्म दर ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में जनसंख्या दर 4.3 से 2.9 हुई है। इस दर को 2 तक करने के तरीके और महत्ता को बताने के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री ने अश्लील भाषा और असंसदीय शब्द का प्रयोग किया। इस मुद्दे की गंभीरता को सिरे से नकारते मुख्यमंत्री जी ने बायोलॉजिकल प्रक्रिया का सड़क छाप बखान कर दिया।

राजनीति में सेमीफाइनल कुछ नहीं होता

अजय सेतिया

वर्ष 2003 के अंतिम महीने में जब भाजपा ने मध्यप्रदेश के साथ साथ कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी जीत लिया था, तो भाजपा ने उन नतीजों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल समझ लिया था। इसीलिए प्रमोद महाजन जैसे सलाहाकारों की सलाह पर अटल बिहारी वाजपेयी ने चार महीने पहले ही लोकसभा चुनाव करवा दिए थे। अक्टूबर 2004 में होने वाले चुनाव अप्रेल 2004 में करवा दिए थे। नतीजा यह निकला कि लगातार दो बार से जीत रही भाजपा की सीटें कांग्रेस से घट गईं, और यूपीए की सरकार बन गई।

2018 में भाजपा मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक चारों राज्यों में हार गई थी, लेकिन सिर्फ पांच महीने बाद हुए लोकसभा चुनावों में इन्हीं चारों राज्यों से भाजपा को बंपर सीटें मिलीं। अब जो यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पांच में से तीन राज्यों में चुनाव जीत गई, तो केंद्र में उसे कोई नहीं रोक सकेगा, वह उन लोगों की खामख्याली है, जो यह भविष्यवाणी कर रहे हैं। राजनीतिज्ञों में यह खामख्याली हमेशा बनी रहती है, लेकिन अब खामख्याली का दायरा पत्रकारों में बढ़ता जा रहा है।

पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट्स और अखबारी विश्लेषणों में यह देखने को मिल रहा है कि इस महीने होने वाले विधानसभा चुनावों को अप्रेल-मई 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल कह रहे हैं। कुछ महीने पहले ऐसी राजनीतिक अपरिपक्वता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दिखाई थी, जब उन्होंने दिल्ली सेवा बिल को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बता दिया था। इस बहाने वह विपक्षी दलों से संपर्क साध कर पहली लाईन में आकर जरुर खड़े हो गए, लेकिन संसद से पारित होने वाला कोई बिल लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल नहीं हो सकता।

कांग्रेस पांचों विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल की तरह लड़ रही है। पांचो राज्यों के चुनावों से पहले उसने विपक्षी एकता की सारी कोशिशें बंद कर दी है। कहीं किसी भी राज्य में इंडी एलायंस के सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हो रही। जब शुरुआती बात हुई थी तो अखिलेश यादव और केजरीवाल जैसे सहयोगी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस को अपनी हैसियत में रखने की कोई कोशिश कर रहे थे।

इसलिए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव नतीजों तक इंडी एलायंस को ठंडे बस्ते में डाल दिया और सीट शेयरिंग पर बात बिलकुल बंद कर दी। यहाँ तक कि विधानसभा चुनावों के दौरान इंडी एलायंस की साझा रैली का इरादा भी त्याग दिया। इस पर विपक्षी एकता की पहल करने वाले नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं।

पिछले गुरूवार को पटना में हुई सीपीआई की रैली में नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस इंडी एलायंस की अगली मीटिंग और सीट शेयरिंग में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि वह तो कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन उसकी सोच पांच विधानसभाओं के चुनावों में अटकी है। कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय नेता ने उनके बयान पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने नीतीश कुमार पर फब्ती कसते हुए कहा कि वह नरेंद्र मोदी को एक दो दिनों में प्रधानमंत्री पद से हटाने के सपने ले रहे हैं। लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाव तो अगले साल अप्रेल मई में हैं। कांग्रेस के रणनीतिकार यह मान कर चल रहे हैं कि अगर कांग्रेस पांच में से तीन राज्य जीत गई, तो विपक्ष में उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है, तो वह आधी लड़ाई तो लोकसभा से पहले ही जीत जाएगी। क्योंकि कांग्रेस के सामने फिलहाल खुद को विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित करने का संकट है। कांग्रेस की इस रणनीति को इंडी एलायंस के पार्टनर भी उस समय पूरी तरह समझ गए, जब कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में सहयोगी दलों के लिए सीटें छोड़ने से इंकार कर दिया। नतीजा यह निकला कि अरविन्द केजरीवाल ने तो गुजरात की तरह कांग्रेस को सब राज्यों में हराने के लिए बड़ी मात्रा में उम्मीदवार खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के पडौसी राज्य मध्यप्रदेश में छह सीटें मांगी थीं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें छह सीटें देना तो दूर, कमलनाथ ने मीडिया के सामने छोड़ो अखिलेश वखिलेश कह कर उन्हें अपमानित भी किया।

अपने अपमान का बदला लेने के लिए अखिलेश यादव ने 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए और अब कांग्रेस के खिलाफ जम कर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस नेता मध्यप्रदेश में सपा की हैसियत की बात कर रहे हैं, तो वह यूपी में कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में जिस तरह एक दो विधानसभा सीटों की हैसियत समाजवादी पार्टी की है, यूपी में वैसी ही हैसियत कांग्रेस की है। वह भी विधानसभा चुनाव में दो ही सीटें जीती थीं। नीतीश कुमार भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी मध्यप्रदेश में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए जेडीयू के पांच उम्मीदवार उतार दिए हैं।

दूसरी तरफ वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को सेमीफाइनल समझ कर लड़ती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक हारने और उसके बाद इंडी एलायंस बनने के बाद भाजपा भी इन विधानसभा चुनावों को गंभीरता से सेमीफाइनल की तरह ले रही है। इन पांच राज्यों में भाजपा की सिर्फ एक राज्य मध्यप्रदेश में सरकार में है, जबकि कांग्रेस दो राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता में है। बाकी दोनों राज्यों तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। भाजपा हालांकि तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसकी प्राथमिकता यह है कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस सत्ता में न आए, इसलिए वह चाहती है कि प्रादेशिक पार्टियां दुबारा सत्ता में लौटें। भाजपा बाकी तीनों राज्यों में कांग्रेस से खुद लड़ रही है, वैसे तो उसकी कोशिश है कि तीनों राज्यों में उसकी सरकार बन जाए, तो कर्नाटक और ईंडी एलायंस से बनी कांग्रेस की हवा गायब हो जाएगी। इसलिए भाजपा ने कांग्रेस की बढ़त वाले छत्तीसगढ़ में पूरा जोर लगा दिया है। जबकि राजस्थान और मध्यप्रदेश में जहां शुरू में नेतृत्व परिवर्तन के संकेत दिए जा रहे थे, उन संकेतों में अब काफी कमजोरी दिखाई दे रही है। भाजपा ने मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे के हाथ में चुनावी बागडोर सौंप दी है, ताकि इन दोनों राज्यों को हर हाल में जीत कर सेमीफाइनल जीतने का संदेश दे दिया जाए।

भाजपा की कोशिश अपना कम से कम एक राज्य बढ़ाने और कांग्रेस का एक राज्य घटाने की है, जबकि कांग्रेस का जोर भाजपा से मध्यप्रदेश छीनने और राजस्थान छत्तीसगढ़ बचाने पर है, ताकि तीन राज्य जीत कर वह यह संदेश दे सके कि वह लोकसभा चुनावों में विपक्ष का नेतृत्व करने की क्षमता रखती है। वैसे तो लोकसभा चुनावों का कोई सेमीफाइनल नहीं होता, लेकिन अगर भाजपा मध्यप्रदेश न बचा पाई और राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में से एक राज्य नहीं जीती तो लोकसभा चुनावों में इंडी एलायंस के हौंसले बढ़े हुए होंगे। दूसरी तरफ भाजपा के समर्थकों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जबसे वह प्रधानमंत्री बने हैं, क्षेत्रीय नेताओं को दरकिनार किया गया है। ऐसे नतीजों से यह संदेश जाएगा कि लोकसभा चुनाव तो ठीक, वह तो मोदी के नेतृत्व में भाजपा 2024 में फिर जीत जाएगी, लेकिन राज्यों में चुनाव जिताने की क्षमता मोदी में नहीं है। संघ परिवार में भाजपा की कार्यशैली पर पुनर्विचार भी होगा कि उसे सामूहिक नेतृत्व की ओर वापस लौटना चाहिए।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-37)

गतांक से आगे...

जो मनुष्य संकल्परूप वासना को मूलसहित छोड़कर परमशक्ति को प्राप्त होता है, उसी का वह श्रेष्ठ त्याग समझने योग्य है। उसी को मुक्त हुआ तथा ब्रह्मवेत्ताओं में अनुपम जानो।

ये दोनों ही ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त करते हैं, ये ही दोनों सांसारिक ताप से मुक्त हैं। हे मुने! शम-दम से युक्त संन्यासी एवं योगी किसी भी काल में आ पड़ने वाले सुखों व दु:खों से युक्त नहीं होते। जिसके अन्त:करण में इच्छा एवं अनिच्छा दोनों ही समाप्त हो गई है और जो सुषुप्तावस्था का आचरण करता है, वही पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है; जो वासनाओं से रहित है, वह हर्ष, अमर्ष, भय, क्रोध, काम एवं कार्पण्य की दृष्टि से न तो आनन्दित होता है और न ही दु:खी होता है। जो तृष्णा बाहर के विषयों की वासना से प्रकट होती है, वह बन्धन डालने वाली कही गयी है। जो तृष्णा सभी तरह के विषयों की वासना से रहित होती है, वह मोक्ष प्रदाता होती है। प्रार्थना के द्वारा किसी भी वस्तु के प्राप्ति की कामना ही दु:ख, भय एवं जन्म प्रदात्री होती है। उसे घोर बन्धनस्वरूपा जानो। महात्माजन सत-असत्रूप समस्त पदार्थों की इच्छा-आकांक्षा का हमेशा के लिए पूर्णरूपेण परित्याग करके परमउदार पद को प्राप्त करते हैं। बन्धन की सत्ता में आस्था एवं मोक्ष की आस्था तथा सुख-दु:ख स्वरूपा सत् एवं असत् की आस्था विश्वास का सदैव के लिए त्याग करके प्रशान्त महासागर के सदृश प्रतिष्ठित हो जाओ। हे महात्मन्! पुरुष के चार तरह के निश्चय होते हैं, जिनमें से प्रथम निश्चय यह है कि पैर से सिर तक मेरी संरचना मेरे माता-पिता के संयोग से हुई है। हे ब्रह्मन्! अब द्वितीय निश्चय सुनें। बन्धन में दु:खों का अवलोकन कर मैं सभी तरह के जागतिक प्रपञ्चों विकारों से परे बाल के अग्रभाग से भी अतिसूक्ष्म आत्मा हूँ। यह निश्चय ज्ञानीजनों को मोक्ष दिलाने वाला कहा गया है। हे विप्रवर! तृतीय निश्चय यह है कि मैं सम्पूर्ण चराचर जगत् के पदार्थों की आत्मा हूँ, सर्वरूप एवं क्षयरहित हूँ इस प्रकार से यह तीसरा निश्चय मनुष्य की मुक्ति का विशेष कारण होता है। अब चौथा निश्चय सुनें, मैं या जगत् सभी कुछ आकाश की भाँति शून्य है। यह चतुर्थ निश्चय पुरुष के लिए मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। इनमें से प्रथम निश्चय बन्धन में बाँधने वाला तथा तृष्णा (बन्धनभूता) से युक्त है। शेष तीनों निश्चय स्वच्छ, शुद्ध तृष्णा (बन्धनरहित) से समन्वित होते हैं तथा इन तीनों निश्चयों से युक्त मनुष्य जीवन्मुक्त एवं आत्मतत्त्व में विलास करने वाले होते हैं।

क्रमश: ..

दत्तोपंत ठेंगड़ी ने श्रम को पूंजी का दर्जा देकर आर्थिक विकास को गति दी

प्रह्लाद सबनानी

श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का जन्म 10 नवम्बर, 1920 को, दीपावली के दिन, महाराष्ट्र के वर्धा जिले के आर्वी नामक ग्राम में हुआ था। श्री दत्तोपंत जी के पित्ताजी श्री बापूराव दाजीबा ठेंगड़ी सुप्रसिद्ध अधिवक्ता थे तथा माताजी श्रीमती जानकी देवी गंभीर आध्यात्मिक अभिरूची से सम्पन्न थीं। 22 मार्च 1942 को संघ के प्रचारक का चुनौती भरा दायित्व स्वीकार कर आप सुदूर केरल प्रान्त में संघ का विस्तार करने के लिए कालीकट पहुंच गए थे। वर्ष 1949 में परम पूजनीय श्री गुरुजी ने देश में श्रमिकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए श्री दत्तोपंत जी को श्रम क्षेत्र का अध्ययन करने को कहा। इस प्रकार श्री दत्तोपंत जी के जीवन में एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ। श्री दत्तोपंत जी ने इंटक में प्रवेश किया। अपनी प्रतिभा और संगठन कौशल के बल पर थोड़े समय में ही इंटक से सम्बधित नौ युनियनों ने श्री दत्तोपंत जी को अपना पदाधिकारी बना दिया। कम्यूनिस्ट यूनियन्स और सोशलिस्ट यूनियन्स की कार्य पद्धति जानने के उद्देश्य से 1952 से 1955 के कालखंड में आप कम्युनिस्ट प्रभावित एक मजदूर संगठन के प्रांतीय संगठन मंत्री रहे। इसी कालखंड में (1949 से 1955) आपने कम्युनिज्म का गहराई से अध्ययन किया।

आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में साम्यवाद एवं पूंजीवाद दोनों ही विचारधाराएं भौतिकवादी हैं और इन दोनों ही विचारधाराओं में आज तक श्रम एवं पूंजी के बीच

सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया है। इस प्रकार, श्रम एवं पूंजी के बीच की इस लड़ाई ने विभिन्न देशों में श्रमिकों का तो नुकसान किया ही है साथ ही विभिन्न देशों में विकास की गति को भी बाधित किया है। आज पश्चिमी देशों में उपभोक्तावाद के धरातल पर टिकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं पर भी स्पष्टत: खतरा मंडरा रहा है। 20वीं सदी में साम्यवाद के धराशायी होने के बाद एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि साम्यवाद का हल पूंजीवाद में खोज लिया गया है। परंतु, पूंजीवाद भी एक दिवास्वप्न ही साबित हुआ है और कुछ समय से तो पूंजीवाद में छिपी अर्थ सम्बंधी कमियां धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी हैं। पूंजीवाद के कट्टर पैरोकार भी आज मानने लगे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के दिन अब कुछ ही वर्षों तक के लिए सीमित हो गए हैं और चूंकि साम्यवाद तो पहले ही पूरे विश्व में समाप्त हो चुका है अत: अब अर्थव्यवस्था सम्बंधी एक नई प्रणाली की तलाश की जा रही है जो पूंजीवाद का स्थान ले सके। वैसे भी, तीसरी दुनिया के देशों में तो अभी तक पूंजीवाद सफल रूप में स्थापित भी नहीं हो पाया है।

किसी भी आर्थिक गतिविधि में सामान्यत: पांच घटक कार्य करते हैं- भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन एवं साहस। हां, आजकल छठे घटक के रूप में आधुनिक तकनीकि का भी अधिक इस्तेमाल होने लगा है। परंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में चूंकि केवल पूंजी पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है अत: सबसे अधिक परेशानी, श्रमिकों के शोषण, बढ़ती बेरोजगारी, समाज में लगातार बढ़ रही आर्थिक असमानता और मूल्य वृद्धि को लेकर होती है। पूंजीवाद के मॉडल में उपभोक्तावाद एवं पूंजी की महत्ता इस कदर हावी रहती है कि उत्पादक लगातार यह प्रयास करता है कि उसका उत्पाद भारी तादाद में बिके ताकि वह उत्पाद की अधिक से अधिक बिक्री कर लाभ का अर्जन कर सके। पूंजीवाद में उत्पादक के लिए चूंकि उत्पाद की अधिकतम बिक्री एवं अधिकतम लाभ अर्जन ही मुख्य उद्देश्य है अत: श्रमिकों का शोषण इस व्यवस्था में आम बात है। आज तक भी उत्पादन के उक्त पांच/छह घटकों में सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सका है। विशेष रूप से पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के बीच टकराव बना हुआ है। पूंजीपति, श्रमिकों को उत्पादन प्रक्रिया का केवल एक घटक मानते हुए उनके साथ कई बार अमानवीय व्यवहार करते पाए जाते हैं। जबकि श्रमिकों को भी पूंजी का ही एक रूप मानते हुए, उनके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए। इस संदर्भ में राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना कर श्रमिकों को उनका उचित स्थान दिलाने के उद्देश्य से कुछ गम्भीर प्रयास अवश्य किए थे।

मानवता पर बड़ा कुठाराघात है इस्लामिक आतंकवाद

ललित गर्ग

समूची दुनिया मजहबी कट्टरता, अमानवीय अत्याचार एवं उन्मादी आतंकवाद के चलते विश्वयुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। हमास के आतंकवादियों ने किस तरह की हैवानियत की थी, छोटे छोटे बच्चों एवं महिलाओं के साथ घर में घुसकर हिंसा, अनाचार किया, गोली मारी, जिंदा जला दिया। पकड़े गये सैनिकों को बारूद में लपेट कर जीवित जला देना, अपने ही हिमायती लोगों को अपने लिए मानव ढाल बनने के लिए मजबूर करना, उन्हें युद्ध क्षेत्र में रोकना, जिससे अधिक से अधिक लोगों की जान जा सके यह किसी युद्ध की स्थिति नहीं है, यह इस्लामी कट्टरवादी सोच है। यह सारी मानवता को चुनौती है, विश्वशांति को खतरा है, उसके लिए अस्तित्व रक्षा का प्रश्न है। अब सवाल ये है कि गाजा के आम लोगों का इसमें क्या कसूर? क्या हमास की दरिंदगी का बदला गाजा के आम लोगों के खून से चुकाया जाएगा? आखिर कब तक निर्दोष, मासूम एवं आमजन उन्माद एवं आतंक की भेंट चढ़ते रहेंगे? इस्लामी कट्टरता एवं उन्माद के काले दंश केवल गाजा पट्टी में ही नहीं, भारत में भी कहर बरपाते रहे हैं, लम्बे समय से जम्मू-कश्मीर हो या, हाल ही में मणिपुर-मेवात में हुई हिंसा, उन्माद एवं वहशियाना हरकतें चिन्ता का सबब बनती रही है।

इस्लामी आतंकवाद खतरनाक है, मानवता पर कुठाराघात है। इस तरह के आतंक से दुनिया को डराना एवं भयभीत करना मुख्य लक्ष्य है। हमास के आतंकवादियों ने जब इजरायल के मासूम नागरिकों पर बेरहमी से हमला किया तो वो हथियारों के साथ-साथ कैमरों से भी लैस थे, अपनी वहशियाना हरकतों को कैमरे में कैद कर रहे थे। आज जब इसके सबूत

सामने आए तो साफ हो गया कि इरादा सिर्फ मारकाट मचाना नहीं था, इरादा सिर्फ इजरायल को नुकसान पहुंचाने का भी नहीं था, इरादा तो ये था कि ये हैवानियत दुनिया को दिखाई जाए, दुनिया को इस्लाम एवं उसकी आतंकी सोच के सामने झुकने को विवश करना इरादा था, इरादा इजरायल के आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाना भी था।

इजरायल दुनिया को हमास के जुल्मों की तस्वीरें दिखाकर पूछ रहा है कि इस पर दुनिया के इस्लामिक देश खामोश क्यों हैं? जो आज इजरायल से जंग रोकने के लिए कह रहे हैं उन्होंने हमास की अमानवीय कार्रवाई की निंदा क्यों नहीं की? अगर कैमरों पर सबूत न होते तो कुछ लोग शायद ये कह देते कि इजरायल की फौज और मोसाद ने खुद ही अपने लोगों को मरवाया ताकि उन्हें हमास पर हमला करने का बहाना मिल सके। लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत हैं और दावे भी कि हमास के आतंकवादियों ने मासूम और बेकसूर लोगों के साथ वहशियाना तरीके से जुल्म किया, हत्या की और आज भी अगवा किए गए लोगों को इंसानी ढाल बनाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलिस्तीन का समर्थन एवं मानवाधिकार की बातें करने वाले इन हरकतों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। दुनिया के कई मुल्कों में प्रदर्शन हुए हैं, लोग इजरायल पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि वो गाजा पर किए जा रहे हमलों को रोके।

इजरायल के कड़े रुख को देखते हुए अब हमारे देश में भी फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम नेताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। ये वे ही लोग एवं संगठन हैं जो भारत में होने वाली आतंकवादी घटनाओं, उन्मादी सोच एवं हिंसा एवं पाकिस्तानी हरकतों का समर्थन करने से बाज नहीं आते। हमास के दहशतगर्दों ने महिलाओं के कपड़े उतारकर उन पर जुल्म करके, उनकी नुमाइश करते वक्त कैमरों के सामने अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। गौर करने की बात ये भी है कि सऊदी अरब और यूनिइटेड अरब अमीरत के मुल्कों में कोई विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर नहीं उतरा लेकिन हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं-बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। असदुद्दीन ओवैसी खुलकर इजरायल का विरोध कर रहे हैं। इजरायल का समर्थन करने के भारत सरकार के फैसले को गलत बता रहे हैं। पिछले दिनों मेवात में बरपी इस्लामिक कट्टरता में भी गाजापट्टी जैसे ही दृश्य देखने को मिले। जिहादियों ने हिन्दुओं पर हमला करने की पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। यहां तक कि उन्होंने मन्दिर में फंसे हिन्दू महिलाओं, बच्चों एवं निर्दोषों को निकालने के लिये गुरुग्राम से आने वाले पुलिसकर्मियों पर भी हमले किये। पुलिस थाने को भी जला दिया गया, ताकि पुलिसकर्मी रक्षा एवं बचाव कार्य न कर सके। उस समय मेवात मानो मिनी पाकिस्तान बन गया था। मेवात में अल्पसंख्यक हिन्दुओं का कब्रिस्तान बनाने का एक षडयंत्र एवं साजिश थी। मेवात के सभी सैंकड़ों गांव हिन्दू-विहीन हो चुके हैं। मेवात के हालात आज के गाजा पट्टी जैसे ही बने हुए थे। भारत में ऐसे अनेक गाजा पट्टी हैं, जहां इस्लामिक उन्माद चाहे जब फट सकता है। पूरे देश में इस्लामिक कट्टरता एवं जिहादी सोच के चलते मानवीय मूल्यों एवं साम्प्रदायिक सौहार्द का ह्रास हुआ है। हिंसा, आतंक, उन्माद पनपे हैं। इस्लामिक कट्टरता एवं उन्माद से जुड़ी समस्याओं ने नये सन्दर्भों में पंख फैलाये हैं। मानवीय संबंधों के बीच एकता, अखण्डता, सहयोगिता, सह-अस्तित्व, प्रेम, आपसी सौहार्द, करुणा, अहिंसा एवं उदारता की पहचान घटी है। कहना गलत न होगा कि हमास द्वारा इजरायल के निर्दोषों का नरसंहार भारत के कथित धर्मनिरपेक्ष तत्वों को दिखाई नहीं दिया, वे तथा सत्ता विरोधी गठबंधन से जुड़े दल मुस्लिम वोटों की संकीर्ण राजनीति के चलते आतंकियों के विरुद्ध एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सके, आतंक के विरोध में बोलना उनकी मुस्लिम तुष्टिकरण नीति के खिलाफ जो ठहरा। विश्व भर में मानवाधिकारों की बात करने वाले भी आतंकी हमलों का विरोध न करके चुप्पी साथ गए। यही नहीं, आतंकियों के समर्थन में भारत भर में सत्ता के विरोध का वातावरण बनाया गया। अब मानवीय दृष्टिकोण से जब गाजा के सामान्य निर्दोष नागरिकों के लिए भारत ने राहत सामग्री भेजी है, तब हमास के समर्थन में जुलूस निकालने और तकरीर करने वाले तत्वों ने भारतीय सत्ता की तनिक भी सराहना नहीं की। भारत ने विश्व स्तर पर पीड़ित मानवता की सहायता करने में कभी कसर बाकी नहीं छोड़ी, फिर भी खास धर्म के अनुयायियों द्वारा भारत का विरोध करना यही सिद्ध करता है कि भले ही सबका साथ सबका विकास की नीति का अनुपालन करते हुए सत्ता भेदभाव न करती हो, फिर भी कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके लिए धर्म के नाम पर आतंकियों का समर्थन सर्वोपरि है, राष्ट्र दोयम दर्जे पर ही है।

आज का इतिहास

1986 बंगलादेश में संविधान फिर लागू किया गया।
1989 जर्मनी में बर्लिन की दीवार को गिराने का कार्य शुरू हुआ।
2005 यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिकन नेतृत्व बजट योजनाओं से एक प्रावधान को गिराता है जो उदारवादी रिपब्लिकन के विरोध और सीनेट में अपेक्षित विरोध के कारण आर्कटिक नेशनल वाइल्डलाइफ रिफ्यूजी को ड्रिलिंग के लिए खोल देगा।
2006 प्रमुख श्रीलंकाई तमिल राजनेता और मानवाधिकार वकील नादराजा रविराज की कोलंबो में हत्या कर दी गई थी।
2007 ईरान में पुलिस ने लगभग 180 सूफी मुसलमानों को दोषी ठहराया है जो बोरुजर्ड में एक शिया मस्जिद में हमलों के लिए जिम्मेदार थे, जब एक मौलवी ने उनके धर्म को नाजायज बताया।
2008 मंगल ग्रह पर उतरने के पांच महीने बाद लैंडर से संचार बंद हो जाने पर नासा ने फीनिक्स मिशन को समाप्त कर दिया।
2009 Itaipu में एक बिजली की विफलता एक बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट की ओर ले जाती है। इसने ब्राजील के 15 राज्यों और पराग्वे के पूरे देश को थोड़े समय के लिए प्रभावित किया जिससे साओ पाउलो जैसे बड़े शहरों में हंगामा हो गया।
2010 अल सल्वाडोर के इलोबास्को शहर में एक किशोर जेल में आग लग गई। इससे 16 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।
2011 विपक्षी कार्यकर्ताओं के अनुसार, लगभग 38 लोग, जिनमें छह बच्चे शामिल हैं, सीरिया में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए हैं- 16 शहर में होम्स, 10 इदलिब में, छह हमा में, तीन दमिश्क के उपनगरीय इलाके में और तीन दारा में।
2012 सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक फ्रांस्वा बोज़ीज़ के अध्यक्ष फ्रांस्वा बोज़ीज़ ने होटल का बिल देने से इंकार करने पर अपने बेटे को हिरासत में लेने के लिए कहा।
2013 मोटर स्पोर्ट्स में, स्पेन के मार्क मेर्केज ने 20 साल की उम्र में 2013 मोटो जीपी विश्व चैम्पियनशिप में जीत हासिल करने के लिए सबसे कम उम्र के मोटर साइकिल चालक होने का खिताब हासिल किया।

छत्तीसगढ़ चुनाव में सब धान बाइस पसेरी

आलोक पुतुल

छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के दौरान कभी नारा लगाया जाता था, 'छत्तीसगढ़ के बासी म ऊफान हेज' और आज जब वहां पांचवें विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़े दल छत्तीसगढ़ की 'बासी' में उफान लाना चाहते हैं। रात के बचे चावल को पानी में भिगोकर बनाई जाने वाली बासी प्रदेश के लोगों के जीवट को दर्शाती है। यह वही बासी है, जिसे एक मई को श्रमिक दिवस से जोड़कर भूपेश सरकार ने 'बोरे-बासी दिवस' घोषित कर दिया है।

धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में आज खेती और किसान राजनीति के केंद्र में हैं। इसकी शुरुआत पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हो गई थी, जब कांग्रेस पार्टी ने किसानों की कर्जमाफी की न केवल घोषणा की, बल्कि सत्ता में आने के कुछ घंटे बाद ही नवगठित सरकार ने यह कर भी दिखाया था। जहां कांग्रेस ने इस बार भी कर्ज माफी की घोषणा की है, वहीं सब्सिडी को रेवड़ी बताने वाली बीजेपी भी, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल की जगह 3100 रुपये प्रति क्विंटल करने का वादा अपने उस घोषणापत्र में कर चुकी है, जिसे 'मोदी की गारंटी' का नाम दिया गया है। कांग्रेस ने इस साल 3200 रुपये भुगतान का वादा किया है। देश के किसी भी हिस्से में इतनी अधिक कीमत पर धान की खरीदी नहीं होती। 90 सीटों वाली विधानसभा में 71 की संख्या वाली कांग्रेस और 13 सीटों पर सिमटी बीजेपी, दोनों को ही उम्मीद है कि इस बार फिर सरकार धान के खेत से ही निकलेगी।

पहली बार छत्तीसगढ़ियावाद पर जोर देते हुए कांग्रेस सरकार ने पूरे पांच साल स्थानीयता और छत्तीसगढ़िया अस्मिता के उत्सव में गुजारे। मुख्यमंत्री कभी लट्टू चलाते नजर आए तो कभी बांस की गेंड़ी पर चढ़ कर बीजेपी को चुनौती देते। छत्तीसगढ़ महतारी पर आत्मगौरव करने

वाला एक बड़ा वर्ग उभर कर सामने आया। फिर भी, नीतियों के स्तर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच का फर्क कई वजहों से धुंधला होता नजर आता है। गायों के लिए गांव-गांव में गौठान बनाने और गोबर-गोमूत्र खरीदने की सरकारी योजनाओं की सराहना संघ ने भी की। हालांकि धरातल पर इन योजनाओं का बुरा हाल है। राम वन गमन पथ का निर्माण, माता कौशल्या मंदिर का सौंदर्यीकरण, जगह-जगह भगवान राम की विशालकाय मूर्तियों की स्थापना, रामायण महोत्सव, नदी आरती, गांव स्तर पर मानस प्रतियोगिता, राज्य भर में राम रथ यात्रा, शहरों में कृष्ण कुंज, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए रायपुर में बहुचर्चित गोष्ठी जैसे आयोजनों ने लगभग स्थापित कर दिया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी से हिंदुत्व के अधिकांश मुद्दों को छीन लिया है। राज्य में ईसाइयों पर होने वाले हमलों को लेकर भी कांग्रेस ने चुप्पी साधे रखी। सांप्रदायिक तनाव और कर्फ्यू के बाद संघ-बीजेपी के आयोजन के समर्थन में विज्ञापन जारी करने से लेकर, सांप्रदायिक हिंसा में हिंदू-मुसलमान के मारे जाने पर, केवल हिंदू परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की घोषणा जैसे कांग्रेस सरकार के फैसलों ने बार-बार इस बात को स्थापित किया कि कांग्रेस गैर हिंदुओं के साथ नहीं नजर आना चाहती।

माओवाद से निपटने के लिए शांति वार्ता की पहल का कांग्रेस का पांच साल पुराना वादा भी धरा रह गया। शराबबंदी के वादे से तो कांग्रेस सरकार पलटी ही मार गई। इसके उलट सरकार ने दूसरे राज्यों को शराब बेचने की कंसलटेंसी शुरु कर दी। सिंचाई और दूसरी अधोसंरचना के काम हाशिये पर पड़े रहे। ओबीसी को 14 की जगह 27 फ़ीसदी की नई आरक्षण नीति भी धरातल पर नहीं उतर पाई। ऊपर से शराब, कोयला, चावल के हजारों करोड़ के घोटालों, पीएससी घोटाला, ऑनलाइन जुआ-सट्टा जैसे मामलों में पिछले तीन सालों से सरकार बुरी तरह से उलझी हुई है। ईडी, आईटी के साल भर से चल रहे छापों के बीच दो आईएएस, कांग्रेस के कई नेता, पुलिस, अधिकारी, उद्योगपति लंबे समय से जेल में हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

कांग्रेस ने आदिवासी बहुल इलाकों में लागू पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया के कानून में ग्रामसभा से 'सहमति' की जगह 'परामर्श' शब्द को जोड़ कर आदिवासी अधिकारों को और कमजोर कर दिया। खदानों के मामले में एक तरफ राज्य ने चर्चित हसदेव अरण्य के जंगल में एक भी नई कोयला खदान की जरूरत नहीं होने का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। लेकिन दूसरी तरफ खुद ही नई खदानों को स्वीकृति दे दी। ये वही खदानें हैं, जो अनुबंध के अंतर्गत अडाणी समूह के पास हैं। राहुल गांधी भले बीजेपी को अडाणी समूह से जोड़ते रहे हों लेकिन भूपेश बघेल ने सत्ता में आते ही राज्य की खदान भी अडाणी समूह को सौंप दी। आज देश में अडाणी समूह के पास सर्वाधिक कोयला खदानें और पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में हैं। वहीं, उत्तर और दक्षिण के आदिवासी बहुल इलाके में आदिवासियों की नाराजगी का नुकसान कांग्रेस को हो सकता है।

बहरहाल, पांच साल पहले चुनाव हार चुकी बीजेपी पूरे परिदृश्य से लगभग गायब रही। पिछले साल राज्य से बाहर के नेताओं ने आकर कमान संभाली और स्थानीय नेताओं को लगभग हाशिये पर डाल दिया। लेकिन ऐन चुनाव के समय फिर से रमन सिंह को आगे कर दिया गया, फिर से पुराने नेता चुनाव मैदान में उतार दिए गए। बीजेपी अपने 15 साल के कार्यकाल बनाम 5 साल के कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की कोशिश में है। कई सीटों पर छोटी पार्टियां भी कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकती हैं। लेकिन इन सबके बाद भी, मैदानी इलाकों के इस जुमले पर कांग्रेस भरोसा करके चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस तो हारती हुई नजर आ रही है लेकिन बीजेपी अभी जीत के लिए तैयार नहीं है।

क्या कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने कर दी कुछ गलतियां!

आशीष तिवारी

मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में छिंदवाड़ा सीट अहम मानी जा रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इसी विधानसभा सीट से सियासी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। कमलनाथ के छिंदवाड़ा से सियासी मैदान में उतरने से सिर्फ उनकी विधानसभा सीट ही नहीं, बल्कि जिले की सभी सातों सीटों के नतीजे सीधे उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ गए हैं। अमर उजाला डॉट कॉम ने मध्यप्रदेश के इस महत्वपूर्ण जिले की सीटों पर ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जब लोगों से बातचीत की, तो यहां की तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आई। फिलहाल यहां सभी सियासी दल तो अपनी अपनी जीत का दावा कर ही रहे हैं, बल्कि कुछ सीटों पर निर्दलीय भी खेल बिगड़ने की गोटियां सेट कर चुके हैं। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नेता कमलनाथ की तूती बोलती है। पिछले विधानसभा के चुनाव में यहां की सभी सातों सीटों पर कांग्रेस का ही झंडा बुलंद रहा था। हालांकि उपचुनाव में छिंदवाड़ा विधानसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बंटी साहू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को कड़ी टक्कर दी और महज 25 हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा सीट को हार गई थी। इस चुनाव में फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के बंटी साहू मैदान में हैं। अमर उजाला डॉट कॉम से बातचीत के दौरान भाजपा के प्रत्याशी बंटी साहू कहते हैं कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नौ बार के सांसद कमलनाथ पिछले चुनाव में महज 25 हजार वोटों से जीते थे। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल उल्टा है। उनका दावा है कि इस बार चुनाव इतना कड़ा है कि वह कमलनाथ को सियासी मैदान में न सिर्फ हराएंगे, बल्कि जिले की सीटों पर भी भाजपा का परचम लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बंटी साहू कहते हैं कि कमलनाथ मुख्यमंत्री तो मध्यप्रदेश के रहे और खुद को छिंदवाड़ा का सबसे बड़ा हमदर्द भी बताते हैं, लेकिन आप इलाके में जब घूम कर देखेंगे तो यहां विकास और औद्योगीकरण की तस्वीर सामने आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बंटी साहू आरोप लगाते हैं कि कमलनाथ जनता के नेता नहीं है। वह छिंदवाड़ा में ही किसी के सुख और दुख में भी शामिल नहीं होते हैं। यही वजह है कि इस चुनाव में कमलनाथ सिर्फ छिंदवाड़ा में ही कमजोर नहीं पड़े हैं, बल्कि यहां की सभी सातों सीटों पर पार्टी कमजोर है। हालांकि बंटी साहू के इन आरोपों का जवाब देते हुए छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कमलनाथ के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दिगंबर पटेल कहते हैं कि भाजपा यहां पिछले चुनाव में भी हारी थी और इस चुनाव में भी हारेगी। उनका कहना है कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। इस इलाके में जो भी विकास आप देख रहे हैं वह यहां के पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ की वजह से ही हुआ है। छिंदवाड़ा शहर के स्थानीय मोहल्ले समानखेड़ा में रहने वाले राजीव पुष्कर मानते हैं कि इस इलाके में विकास तो कमलनाथ के कार्यकाल में ही हुआ। लेकिन वह इसे पर्याप्त नहीं मानते हैं। पुष्कर कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री का क्षेत्र ऐसा नहीं होता है जैसा छिंदवाड़ा है। वह अपने मोहल्ले की गलियां दिखाते हुए कहते हैं क्या आप उम्मीद करते हैं कि केंद्र में कांग्रेस की सत्ता में रहने वाले बड़े नेता कमलनाथ का यह इलाका हो सकता है। स्थानीय पत्रकार और सियासी जानकार मधुसूदन पवार कहते हैं कि छिंदवाड़ा में इस बार सियासत थोड़ी बदली हुई है। उनका कहना है कि यहां की सात विधानसभा सीटों में से कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें सियासी तस्वीर अलग-अलग बन रही है। इसमें इस जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट भी शामिल है। पवार का कहना है कि अमरवाड़ा आदिवासी बाहुल्य विधानसभा सीट है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने गोंडवाना पार्टी के पूर्व विधायक की बेटी मोनिका बट्टी को भाजपा में शामिल कर टिकट दे दिया। वह कहते हैं कि मोनिका अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं और आदिवासियों की नेता रही हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस यह सोचती रही कि अमरवाड़ा में सियासत का कौन सा दांव चला जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोनिका को टिकट देकर इस विधानसभा सीट पर सियासी बाजी को पलटने की फिलहाल एक कोशिश तो की ही है। हालांकि चुनाव परिणाम बताएंगे कि किसका दांव सफल हुआ या असफल। लेकिन यहां पर कांग्रेस को कड़ी टक्कर तो यहां मिल ही रही है।

जाति गणना पर विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सरकार करेगी मंथन

गुलाम अहमद

लोकसभा चुनाव में जाति के सवाल को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने के विपक्ष के दांव से सतर्क मोदी सरकार आगामी जनगणना में जाति की गिनती कराने के संबंध में पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद मंथन करेगी। अंतिम निर्णय से पहले भाजपा के ओबीसी नेताओं के बिहार जाति गणना के जमीनी स्तर पर प्रभाव संबंधी फीडबैक का इंतजार है। भाजपा नेतृत्व खासतौर से जाति राजनीति की पहचान माने जाने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश से फीडबैक का इंतजार कर रहा है। इस संदर्भ में बीते 2 नवंबर को हुई ओबीसी नेताओं की बैठक में उपस्थित बिहार के वरिष्ठ नेता ने कहा कि बिहार में जाति गणना का जमीनी स्तर पर व्यापक प्रभाव है। बैठक में भी तय हुआ था कि

इसके प्रभाव का आकलन कर ही कोई निर्णय किया जाएगा। जाति जनगणना के बाद नीतीश सरकार ने जिस तरह आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है, उससे लोकसभा चुनाव में जाति का सवाल सबसे अहम हो जाएगा। जाति गणना के संदर्भ में भविष्य में अहम फैसला करने संबंधी संदेश बीते हफ्ते छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के बयान से मिला। छत्तीसगढ़ में शाह ने कहा कि भाजपा ने कभी इसका विरोध नहीं किया है। इसके अलावा सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले राजग के सभी सहयोगी दल और इनके नेता खुल कर जाति गणना की मांग कर रहे हैं। इस संदर्भ में पार्टी नेतृत्व की खास निगाहें बिहार और यूपी पर है। इन दोनों राज्यों में लोकसभा की 120 सीटें हैं और राजनीति में जाति का प्रभाव सबसे ज्यादा है। जाति राजनीति की काट के लिए पार्टी ने दोनों ही राज्यों में सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले कई दलों को जोड़ा है। ओबीसी से जुड़ी उपलब्धियों के व्यापक प्रचार प्रचार, सामाजिक (जाति) सम्मेलन की व्यापक योजना तैयार की है। बिहार में जातीय समीकरण साधने के लिए भाजपा ने चिराग पासवान को अपनी पार्टी का भाजपा में विलय का फिर से प्रस्ताव दिया है। विलय के एवज में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने और बाद में राज्य में पार्टी का चेहरा बनाने का वादा किया गया है। पार्टी की योजना चिराग-जीतन राम मांझी के जरिये दलित वोट बैंक पर एकाधिकार जमाने की है।

योगी राज में विधायिका पर भारी है यूपी की कार्यपालिका

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल सख्त शासक हैं। उनकी छवि काफी साथ-सुथरी है। करीब साढ़े छह: साल के शासनकाल में योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। यह एक अच्छी बात है। जनता भी ऐसी ही सरकार चाहती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि योगी को छोड़कर यूपी के अन्य सभी राजनेता बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं। सभी दलों में अच्छे-बुरे दोनों किस्म के नेता मौजूद हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का भी यही 'मिजाज' है। यहां भी अन्य दलों की तरह दोनों किस्म के नेता देखने को मिलते हैं। मगर बीजेपी आलाकमान को अपने किसी भी नेता पर भरोसा नहीं है। यहां तक की योगी सरकार के मंत्री भी सरकारी मशीनरी के सामने 'पंख कटे' नजर आते हैं। इसकी वजह है कि बीजेपी में सभी नेताओं को एक ही तराजू में तौला जा रहा हैं। कहने को तो उसके तमाम नेता जनप्रतिनिधि होने का भी रूतबा रखते हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह से दंतविहीन बना दिया गया है। यह न तो कभी अपने क्षेत्र में पुलिस उत्पीड़न के शिकार लोगों के पक्ष में थाने जा सकते हैं, न शासन-प्रशासन में बैठे अधिकारी उनकी सुनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी मशीनरी को आदेश दे रखा है कि यदि कोई बीजेपी नेता उनके पास किसी की सिफारिश लेकर आये तो उसकी बात सुनने की आवश्यता नहीं है, बल्कि अधिकारी अपने विवेक से सही गलत का फैसला लें। यह सब बातें किसी फाइल में तो नहीं कोड की गई हैं, परंतु राजनीति के गलियारों में यह चर्चा आम है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उसके (सपा) सांसद/मंत्री/विधायक आदि जनप्रतिनिधि पुलिस और सरकारी मशीनरी पर दबाव बना लेते थे, वैसा दबाव बीजेपी के जनप्रतिनिधि नहीं बना पाते

हैं। होता यह है कि जब भी बीजेपी का कोई नेता किसी सरकारी अधिकारी या पुलिस के पास पहुंचता है तो उसे सीएम योगी का फरमान याद दिला दिया जाता है। या यों कहें उन्हें अपमानित करके वापस भेज दिया जाता है।

हालात यह है कि यूपी सरकार के अधिकारी बीजेपी के किसी भी जनप्रतिनिधि को भाव नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी ऐसे नेताओं से मिलने का टाइम नहीं रहता है। इसको लेकर योगी के पिछले शासन में बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा के अंदर प्रदर्शन भी किया था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की अपने ही जनप्रतिनिधियों से दूरी हमेशा चर्चा में रहती है। यहां तक की दिल्ली भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज की तारीख में पार्टी के अंदर योगी का कद काफी बढ़ा हुआ है, इसलिए उन्हें कहीं से चुनौती भी नहीं मिलती है। इसी के चलते पीड़ितों व आम लोगों से पुलिसकर्मियों के दुर्व्यवहार के मामले तो आए दिन सामने आते रहते हैं। पुलिस अधिकारियों व कर्मियों द्वारा माननीयों से भी अच्छा व्यवहार न किए जाने की शिकायतें बढ़ रही हैं। कहने को तो सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते मिल जाते हैं कि जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान किया जाये। इस बार भी योगी द्वारा माननीयों के प्रति शिष्टाचार व अनुमन्य प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसका असर होते नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में अफसरशाही के चलते केवल आम आदमी ही नहीं मंत्री सांसद और विधायक भी परेशान हैं। यह लोकसेवक लम्बे समय से कार्यपालिका के चलते होने वाली अपनी परेशानी शिकायतों के रूप में सामने रखते रहते हैं। ज्ञातव्य हो, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इंटीग्रेटेड ग्रीवॉन्स रिड्रेसल सिस्टम लागू कर रखा है, जिसे आइजीआरएस पोर्टल के रूप में जाना जाता है। इसमें कोई भी सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत कर सकता है। इस पोर्टल पर पिछले दो वर्षों में आम जनता के अलावा योगी के कई मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने भी कार्यपालिका की शिकायत दर्ज कराके अपनी लाचारी सार्वजनिक की है। जिसमें काफी चौंकाने वाली बाते सामने आई है। इन माननीयों की शिकायत से पता चलता है कि प्रदेश में तमाम अफसर आमजन तो दूर मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बात को भी तवज्जो नहीं देते हैं और उनके सुझाए गए कार्यों को बेहद लेटलतीफी करते हैं। इस बारे में नेता और विधायक कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कभी कोई हल नहीं निकल पाया। गौरतलब हो हाल ही में भी शासन व डीजीपी मुख्यालय द्वारा पुलिसकर्मियों को इसे लेकर निर्देश दिए गये हैं। प्रमुख सचिव, गृह संजय प्रसाद ने सभी पुलिस आयुक्तों, एसएसपी व एसपी को सांसदों व विधानमंडल के सदस्यों के प्रोटोकाल का अनुपालन कराए जाने को कहा हैं। उन्होंने कहा है कि शासन व संसदीय अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रोटोकाल उल्लंघन के मामले लगातार आ रहे हैं। संजय प्रसाद द्वारा कहा गया है कि सभी अधिकारी सांसदों व विधानमंडल के सदस्यों के सीयूजी नंबर अथवा उनके द्वारा नोट कराया गया अन्य मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से अपने मोबाइल में फीड करेंगे तथा काल आने पर उसे रिसीव करेंगे।

मुफ्त की खैरात या कल्याणकारी योजनाएं हैं चुनावी घोषणाएं?

संजय तिवारी

बात 2006 की है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके चीफ करुणानिधि ने वादा किया कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो हर गरीब परिवार को एक रंगीन टेलीविजन देंगें। करुणानिधि चुनाव जीते और अपना वादा भी पूरा किया। गरीब परिवारों को टीवी देने का वादा था लेकिन बाद में हर ग्रामीण परिवार को टीवी सेट बांटे गये। पांच साल के कार्यकाल में उन्होंने टीवी बांटने पर 4,000 करोड़ खर्च किये। हालांकि 2011 में जयललिता की सरकार बनी तो उन्होंने इस मुफ्त टीवी वितरण कार्यक्रम को रद्द कर दिया। लेकिन खुद जयललिता ने 2011 में वोटरों को मुफ्त मोबाइल फोन देने का वादा किया था, इसलिए उन्होंने वह बांटना शुरु कर दिया। तमिलनाडु को हम वह पहला राज्य कह सकते हैं जिसने जनता को मुफ्त में ऐसे सामान देने की शुरुआत की जिसका उस जमाने में क्रेज था। अगर आप तमिलनाडु की राजनीति को देखें तो पायेंगे कि वोटरों को जितना कुछ मुफ्त में देने का वादा वहां किया गया, अन्य किसी राज्य में नहीं। करुणानिधि और जयललिता में होड़ रहती थी कि वोटरों को कितना अधिक से अधिक देने का वादा करके वो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं।

लेकिन यह चलन तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं रहा। समय बदला तो नेताओं ने अपने वादों की लिस्ट भी बदली। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिया जो आज भी योगी फ्री लैपटॉप योजना के नाम पर चल रहा है। वर्तमान वित्तवर्ष में इसके लिए 1800 करोड़ रूपये रखे गये हैं। इसके तहत राज्य का कोई भी छात्र या छात्रा मुफ्त लैपटॉप के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते उसने 12वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत से ऊपर अंक प्राप्त किये हों। इसी के साथ योगी सरकार प्रदेश के 25 लाख नौजवानों को स्मार्टफोन बांटने जा रही है। इसके लिए कुल 949 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया है जिसकी पहली किश्त के रूप में 3 लाख 71 हजार मोबाइल फोन इसी महीने से बांटना शुरु होगा।

योगी सरकार ने 2017 में सरकार बनाते ही किसानों का एक लाख रुपए तक का कर्ज भी माफ कर दिया था। आज जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें हर राज्य में पक्ष विपक्ष के द्वारा चुनाव जीतने के बाद मुफ्त का सामान या सुविधा देने का वादा किया जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत भाजपा द्वारा महिलाओं को 1200 रूपये मासिक दिया जा रहा है लेकिन कांग्रेस का वादा है कि वो सरकार में आई तो इसे बढ़ाकर 1500 रूपये महीना कर दिया जायेगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि सरकार बनाने के बाद घरेलू सिलेण्डर 500 रूपये में देंगे। 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ, 200 यूनिट तक हाफ, विकलांग जनों की पेंशन बढाकर 2000 कर देंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चों को एक से आठ तक 500, नौ और दस में 1000 तथा 11वीं और बारहवीं के समय 1500 रूपये प्रतिमाह देंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान और तेलंगाना में भाजपा हो या कांग्रेस सबने अपनी ओर से मतदाता के लिए कुछ न कुछ आकर्षक वादा किया है। तेलंगाना में केसीआर की सरकार 2 लाख से कम आयवाले परिवारों में लड़कियों के विवाह के समय 1 लाख रुपये की मदद करती है। अब कांग्रेस ने इस पर 10 ग्राम सोना देने का भी वादा किया है। इसके

अलावा बाकी दूसरे वादे तो हैं ही। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन मुफ्त की योजनाओं और घोषणाओं को क्या मुफ्तखोरी कहा जाए या फिर जनकल्याणकारी योजानाएं? देश में मध्य वर्ग से जुड़े बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार आदि इन्हें फ्रीबीज कहकर इसकी आलोचना करते हैं जिसका भार अंततः करदाता की जेब पर पड़ता है। ऐसे ढेरों आंकलन और रिपोर्ट मिल जाएंगे जो यह बताएंगे कि मुफ्त की इन योजनाओं से सरकारी खजाने पर कितना बोझ बढ़ेगा। लेकिन क्या सचमुच ये घोषणाएं सरकारी खजाने पर बोझ होती हैं या फिर इनसे उद्योग बाजार को गति मिलती है? चुनावों के बारे में कहा जाता है कि चुनाव अर्थव्यवस्था में गति पैदा करने का एक बड़ा जरिया बनते हैं। यही वह समय होता है जब राजनीतिक दल दिल खोलकर खर्च करते हैं जिससे बाजार में गति आती है।

लेकिन बात सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं रहती। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए जब व्यापक स्तर पर खरीदारी की जाती है तब उन्हीं टैक्सपेयर्स को व्यापार भी मिलता है जिनसे सामान खरीदकर जनता में बांटा जाता है। इसलिए जो लोग ऐसी योजनाओं की फ्रीबीज कहकर आलोचना करते हैं वो सिक्के का दूसरा पहलू कभी नहीं देख पाते।

भारत एक आर्थिक गैर बराबरी वाला देश है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि भारत में शीर्ष के 10 प्रतिशत लोगों के पास कुल वेल्थ का 77 प्रतिशत है। इसमें भी जो 73 प्रतिशत वेल्थ निर्मित हुआ वह शीर्ष के 1 प्रतिशत लोगों तक सिमटकर रह गया। भारत में आर्थिक गैर बराबरी का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की किसी बड़ी कंपनी में एक शीर्ष का सीईओ एक साल में जितनी सैलेरी पाता है उतना पैसा कमाने में एक सामान्य मजदूर को 950 साल लग जाएंगे। यही कारण है कि शीर्ष के 10 प्रतिशत लोगों में और नीचे के पायदान पर खड़े 70 करोड़ लोगों की आमदनी में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है।

एचसीएल टेक्नॉलाजी के एस विजयकुमार इस समय सालाना 124 करोड़ की सैलेरी ले रहे हैं जो सर्वाधिक वेतन पानेवाले कर्मचारी हैं। इस तरह उनकी औसत सैलेरी प्रतिदिन 3 करोड़ रूपये बैठती है जबकि इसी देश में आज भी मनरेगा में काम करनेवाले एक मजदूर की दैनिक मजदूरी 230 रूपया है। ऐसी भीषण गैर बराबरी वाली अर्थव्यवस्था में अगर जनता के एक बड़े वर्ग को सरकारी योजनाओं के नाम पर राहत पहुंचा दी जाती है तो क्या इन्हें फ्रीबीज या मुफ्तखोरी कहकर खारिज किया जाना चाहिए? वह भी तब जब इससे परोक्ष रूप से व्यापारी वर्ग और बाजार ही लाभार्थी होता है तब भी इसकी आलोचना क्यों होनी चाहिए?

बाजारवाद के सिद्धांत के अनुसार ही वह निरंतर अनटैप और अनआर्गेनाइज मार्केट को टैप करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह निरंतर ऐसे सेक्टर की तलाश में रहता है जहां जनसामान्य असंगठित रूप से कारोबार करता है। कंपनियां उसे आर्गेनाइज्ड मार्केट के नाम पर टैप करती हैं और खुदरा प्लेयर को बाहर कर देती है। इससे एक ओर तो व्यापार का ग्राफ बढ़ता दिखाई देता है दूसरी ओर पूंजी का केन्द्रीकरण बढ़ता है और बेरोजगारी बढ़ती है। यह स्थिति मार्केट के उन प्लेयर्स के लिए एक चुनौती है जो पूंजी के इस केन्द्रीयकरण का कारण होती है। इसलिए राजनीतिक दलों की मुफ्त योजनाओं को कल्याणकारी योजनाएं ही कहना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा हो या फिर मुफ्त अनाज योजना। ये सब समाज के उस वर्ग को राहत देते हैं जिनके पास उसे वहन करने की क्षमता नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ऐसी योजनाएं व्यापारी समाज को भी लाभ पहुंचाती है जो प्रत्यक्ष रूप में डॉयरेक्ट टैक्स पैयर होता है। इसलिए राजनीतिक दलों द्वारा शुरु की जानेवाली ऐसी योजनाएं अंततः सबके लिए लाभकारी होती हैं। जिन्हें कुछ मिलता है उनके लिए भी, और जो दल ये सब देकर सत्ता में आते हैं उनके लिए भी। टैक्सपेयर व्यापारिक जगत भी इसका लाभार्थी होता है क्योंकि ऐसी योजनाओं से उनका माल एकमुश्त बिक जाता है। हां, ऐसी योजनाओं में सरकारी भ्रष्टाचार जरूर होता है और नागरिक से ज्यादा लाभ नौकरशाही उठा लेती है। ऐसी योजनाओं का विरोध और आलोचना करने की बजाय इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने का कुछ उपाय जरुर किया जाना चाहिए।

तिल के तेल का दीपक जलाने से ग्रहों की स्थिति होती है ठीक

हिंदू धर्म में पूजा के दौरान दीपक जलाना जरूरी माना गया है। पूजा के दौरान देवी-देवताओं के समक्ष अलग-अलग प्रकार के दीपक जलाए जाते हैं। घी और सरसों के तेल की तरह ही तिल के तेल का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साधक को इससे क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं।

सनातन धर्म में ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए पूजा-अर्चना करने के विधान है। इस दौरान दीपक जलाना भी जरूरी माना जाता है। दीपक के बिना पूजा अधूरी समझी जाती है और भगवान के सामने घी का तेल का दीपक जलाकर पूजा संपन्न की जाती है। हिंदू धर्म में अलग-अलग तेल का दीपक जलाने का अपना-अपना महत्व है। आज हम तिल के तेल का दीपक जलाने से होने वाले लाभ के बारे में बात करेंगे।

शुद्ध होता हा वातावरण

तिल का तेल के दीपक जलाने से वातावरण में व्याप्त नकारात्मकता समाप्त होती है, जिससे वातावरण शुद्ध बना रहता है। जिससे साधक को मानसिक शांति प्राप्त होती है।

प्रसन्न होती हैं मां लक्ष्मी

मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती हैं। साथ ही इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश नहीं होता है।

ज्योतिष शास्त्र के उपाय

तिल का तेल के दीपक जलाने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिससे साधक के कार्यक्षेत्र में तरक्की के योग बनते हैं। साथ ही इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है।

इन बातों का रखें ध्यान

तिल के तेल का दीपक जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे तिल के तेल का दीपक जलाने के लिए लाल धागे की बत्ती सबसे अच्छी मानी जाती है। तिल के तेल का दीपक देवी-देवताओं की बाईं हाथ की तरफ जलाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए, वरना इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता।

हिंदू पौराणिक कथाओं के रहस्यमयी जीव, रोचक है इनके जन्म की कहानी

हिंदू धर्म की पौराणिक कथाएं जानवरों, राक्षसों और अन्य पौराणिक प्राणियों की कहानियों से भरी हुई हैं। हांलाकि इनके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन पुरानी किंवदंतियों में मौजूद कई पौराणिक जीव-जंतुओं के बारे में बताया जाता है।

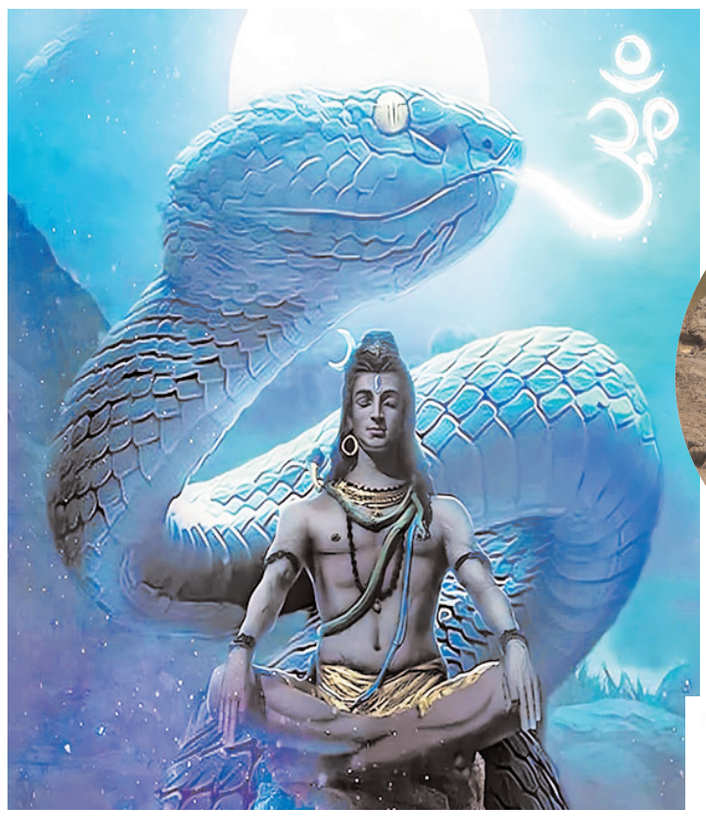

हिंदू धर्म की पौराणिक कथाएं काफी ज्यादा दिलचस्प हैं। यह कहानियां बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक कथा में सिर्फ देवी-देवता ही नहीं बल्कि कई अलग-अलग प्रकार के जीव-जंतुओं, जानवरों और राक्षसों का भी वर्णन किया गया है। हांलाकि इनके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन पुरानी किंवदंतियों में मौजूद कई पौराणिक जीव-जंतुओं के बारे में बताया जाता है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ऐसे में कुछ जीव-जंतुओं के बारे में बताने जा रहे हैं। जिनका हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में वर्णन किया गया है।

ऐरावत

बता दें कि ऐरावत हाथी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐरावत हाथी के जन्म की कहानी नहीं जानते होंगे। जब सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा ने अंडे के छिलके के दो हिस्सों पर सात पवित्र भजन गाए। तो जिसमें से गरुड़ के साथ सात नर और आठ मादा हाथियों का जन्म हुआ था। इस तरह से तीन मुंह वाले ऐरावत हाथी का जन्म हुआ। एक अन्य किंवदंती के मुताबिक दूध के सागर का मंथन के दौरान ऐरावत हाथी निकला था। यह काफी शक्तिशाली और बुद्धिमान था, जो हमेशा भगवान इंद्र के साथ रहता था।

वृत्र अहि

हिंदू पौराणिक कथाओं का एक ड्रैगन वृत्र अहि है। इस राक्षस दुर्भाग्य का राक्षस माना जाता है। एक बार वृत्र अहि राक्षस ने धरती का सारा पानी पी लिया और एक पहाड़ी में जाकर छिप गया। जिसके बाद भगवान इंद्र ने ऐरावत हाथी की मदद से उस राक्षस को हराया और फिर धरती की उर्वरता और पानी को बहाल किया गया।

चकोरा

चकोरा एक ऐसा पक्षी है, जिसको चंद्रमा को काफी बड़ा भक्त माना जाता है। चकोरा पक्षी चांद की तरफ देखता रहता है। जिसके कारण उसकी गरदन तक अकड़ जाती है। कई बार वह चांद को देखते-देखते मर भी जाता है, लेकिन वह चांद को देखना बंद नहीं करता है। बताया जाता है कि चंद्रमा को चकोरा ने फलियां बनाई थीं।

मकर

बता दें कि मकर एक संरक्षक उभयचर है। जिसके मछली की पूंछ के साथ हिरन, मगरमच्छ या हाथी के चेहरे के साथ प्रस्तुत किया जाता है। प्राचीक किंवदंतियों के मुताबिक मकर समुद्र देवी वरुणा की सवारी के रूप में काम करता है।

नंदी

देवताओं ने भगवान शिव को शांत करने के लिए कामधेनु और कश्यप के पुत्र नंदी को उपहार में दिया था। सभी गायों की माता कामधेनु की कई संतानों का दूध भगवान शिव के पेट में भर जाने के कारण उनका ध्यान भंग हो गया था। जिसके

कारण भगवान शिव अंत्यंत क्रोधित हो गए थे। इस कारण उन्होंने अपनी तीसरी आंख

का वार सभी गायों पर कर दिया था।

नवागुंजरा

नवागुंजरा का सिर मुर्गे का और हाथी, बाघ और घोड़े के तीन पैर होते हैं। वहीं इसका चौथा अंग कमल पकड़े हुए एक इंसान की तरह होता है। इस प्राणी की कूबड़ ऊँट की, पूँछ साँप की, गर्दन मोर की और कमर शेर की थी। बताया जाता है कि जंगल में शिकार करते समय अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भगवान कृष्ण ने यह रूप धारण किया था।

इंद्रधनुष मछली

एक बड़े जलीय जीव के रूप में इंद्रधनुष मछली को परिभाषित किया गया है। इस मछली के चार रंग लाल, हरे, पीले और नीले रंग के तराजू हैं। जिनका अर्थ अग्नि, पृथ्वी, वायु और बर्फ है। बताया जाता है कि मछली ने बुद्ध को निगल लिया था। लेकिन फिर बुद्ध को बचा लिया गया तो एक साल तक मछली ने पूरे देश को भोजन उपलब्ध कराया।

शरभा

असुर राजा हिरण्यकश्यप को मारने के लिए एक बार नरसिम्हा ने शेर-मानव के रूप में अवतार लिया था। यह भगवान विष्णु का क्रोधित अवतार था। देवता ने इस अवतार को शांत करने के लिए भगवान शिव को भेजा था। जिसके बाद भगवान शिव ने नरभक्षी पक्षी, विशाल और भयावह का रूप धारण किया था। जो नरसिम्हा को खरोंच कर दूसरे देश में ले गए थे।

शेषनाग

शेषनाग के 1000 कष्टकारी भाई हुआ करते थे। जो सभी के लिए समस्याएं पैदा किया करते थे। इसलिए शेषनाग दुखी होकर हिमालय चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। शेषनाग की तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें उनकी इच्छानुसार आध्यात्मिकता का सेवक बनने का आशीर्वाद दिया था। तब से पृथ्वी को स्थिर रखने के लिए शेषनाग उसके चारों ओर कुण्डली लगाते हैं।

वासुकी सांप

समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने पिया था। लेकिन इस विष को पीने में सांपों ने भगवान शिव की मदद की थी। इसलिए सांपों के सम्मान में भगवान शिव ने सर्पों के राजा वासुकी को अपने गले में डाल लिया था। वासुकी सर्प भगवान शिव द्वारा पिए गए जहर को नीचे उतरने से रोकता है।

धनतेरस के दिन भूल से भी न खरीदें ये चीजें, झेलनी पड़ सकती है आर्थिक तंगी

धनतेरस हिन्दू धर्म का प्रमुख पर्व है। यह पर्व दिवाली से दो दिन पहले मनाया जाता है। इस साल धनतेरस का पर्व 10 नवंबर को है। धनतेरस के दिन पारंपरिक तौर पर मां लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान धन्वंतरि पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और अच्छे से सजाते हैं। साथ ही धन और धन-संपत्ति में वृद्धि के लिए इस दिन घरों में विशेष पूजा-आराधना की जाती है। धनतेरस के दिन विशेष रूप से लोग सोने और चांदी के आभूषण, मूर्तियां या अन्य वस्तुओं की खरीददारी करते हैं, क्योंकि इसे धन की वृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। वैसे तो इस दिन खरीदारी का बड़ा महत्व है, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है, जिन्हें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में...

लोहा

धनतेरस के दिन लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं घर लाना शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन लोहे से बनी कोई भी वस्तु घर लाते हैं, तो घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो जाता है और ये शुभ फल नहीं देता है।

एल्युमिनियम और स्टील

धनतेरस पर एल्युमिनियम या स्टील की वस्तुएं न खरीदें। मान्यता है कि स्टील या एल्युमिनियम से बने बर्तन या अन्य कोई सामान खरीदने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है।

प्लास्टिक

धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन घर में कोई भी प्लास्टिक की चीज लेकर आएंगे तो इससे धन के स्थायित्व और बरकत में कमी आ सकती है।

कांच

धनतेरस के शुभ अवसर पर शीशे या कांच की बनी चीजें भी बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। शीशे या कांच का सीधा संबंध राहु से होता है। मान्यता है कि यदि घर में राहु प्रवेश कर जाए तो इससे तरक्की रूक जाती है।

पत्नी के श्राप के कारण नहीं होती है ब्रह्मा जी की पूजा, पुष्कर में है एकमात्र मंदिर

सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का महत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है। भारत में ब्रह्मा जी का एक मंदिर हैं। जिसके पीछे एक प्रचलित कहानी है।

सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का महत्व बहुत ज्यादा है। जहां श्रीहरि विष्णु को जगत का पालनहार, भगवान शिव को संसार के संहारक और ब्रह्मा जी को संसार के रचनाकार के रूप में जाना जाता है। हमारे देश में विष्णु जी और शिव जी के कई मंदिर स्थित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है। भारत में ब्रह्मा जी का एक मंदिर हैं। जिसके पीछे एक प्रचलित कहानी है। आइए जानते हैं संसार के रचनाकार ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर क्यों है।

पौराणिक कथा

पद्म पुराण के मुताबिक एक बार वज्रनाश नामक राक्षस ने धरती पर उत्पात मचा रखा था। वज्रनाश के अत्याचार इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि ब्रह्मा जी को तंग आकर उसका वध करना पड़ा। जब ब्रह्मा जी ने उस दैत्य का वध किया तो उनके हाथों से तीन जगहों पर कमल का पुष्प गिरा। वह कमल का पुष्प जिन तीन जगहों पर गिरा, वहां पर तीन झीलें बन गईं। जिसके बाद उस स्थान का नाम पुष्कर पड़ गया। वहीं संसार की भलाई के लिए ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर यज्ञ करने का फैसला लिया।

जब ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुचे तो उनकी पत्नी सावित्री समय पर नहीं पहुंच पाईं। यज्ञ पूरा होने के लिए ब्रह्मा जी के साथ सावित्री जी का साथ में होना बहुत जरूरी था। ऐसे में जब सावित्री जी समय पर यज्ञ में नहीं पहुंची तो ब्रह्मा जी ने एक एक गुर्जर समुदाय की कन्या गायत्री से विवाह कर लिया। जिसके बाद मौके पर देवी सावित्री भी मौके पर पहुंच गए। जब सावित्री ने ब्रह्मा जी के बगल में गायत्री को बैठे देखा तो वह क्रोधित हो गईं।

फिर ब्रह्मा जी को सावित्री जी ने श्राप दिया कि वो एक देवता जरूर हैं लेकिन कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा। यह सुन मौके पर मौजूद देवगण अचंभित हो गए। सभी ने सावित्री से निवेदन किया कि वह अपना श्राप वापस ले लें। लेकिन सावित्री जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। हांलाकि जब सावित्री का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी की पूजा पुष्कर में की जाएगा। वहीं जब कोई दूसरा व्यक्ति ब्रह्मा जी का मंदिर बनाएगा तो उस मंदिर का विनाश हो जाएगा। इस काम में ब्रह्मा जी की विष्णु जी ने भी मदद की। जिसके कारण देवी सरस्वती ने भी जगत के पालनहार विष्णु को श्राप दे दिया कि उन्हें भी अपनी पत्नी से विरह का कष्ट सहना पड़ेगा। इसी वजह से भगवान विष्णु ने श्रीराम का अवतार लिया और 14 साल के वनवास के दौरान उन्हें पत्नी वियोग सहना पड़ा था। इसीलिए सिर्फ पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। मान्यता के मुताबिक पुष्कर में ब्रह्मा जी का यह मंदिर एक हजार दो सौ साल पहले बनवाया गया।

बच्चे के जन्म के बाद क्यों किया जाता है कुआं पूजन

हिंदू धर्म में कुआं पूजन की परंपरा का विशेष महत्व होता है। कुआं पूजन पुत्र प्राप्ति पर किया जाता है। साथ ही यह ग्रह-नक्षत्रों को शांति के लिए भी किया जाता है। खासतौर से मूल नक्षत्रों में जन्मे बच्चों के लिए यह पूजा जरूरी मानी गई है। कई स्थानों पर इसे जल पूजा या जलवा पूजा भी कहा जाता है।

कुआं पूजन की परंपरा को नवजात शिशु और मां दोनों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना गया है। साथ ही यह भी माना गया है कि इस परंपरा की शुरुआत भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से हुई थी जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता यशोदा ने कृष्ण जी के जन्म के ग्यारहवें दिन जलवा पूजा की थी यानी जल अर्थात कुआं पूजा किया था। तभी ये परंपरा चली आ रही है।

कब किया जा सकता है कुआं पूजन

रिक्ता तिथि यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को छोड़कर, अन्य किसी भी तिथि पर कुआं पूजन संस्कार किया जा सकता है। वहीं, कुआं पूजा के लिए सोमवार, बुधवार और गुरुवार का दिन अच्छा माना गया है।

साथ ही चैत्र और पौष चंद्र महीनों को छोड़कर, सभी चंद्र महीने कुआं पूजा अनुष्ठानों किया जा सकता है। मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, मूल और श्रवण नक्षत्र भी कुआं पूजन संस्कार के लिए अच्छे माने जाते हैं। हिंदू धर्म में शादी-विवाह संस्कारों में भी बच्चे का कुआं पूजन किया जाता है।

कुआं पूजन विधि

कुआं पूजन के अवसर पर कृष्ण मंदिरों में पूजा-अर्चना की जाती है और भगवान कृष्ण की मूर्ति को सूप में रखकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। कुआं पूजन के दिन सबसे पहले बच्चे और मां को गुनगुने पानी से स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। इसके बाद बच्चे की मां या घर की बड़ी महिला माथे पर एक खाली कलश और चाकू रखकर आसपास के कुएं तक यात्रा की जाती है।

साथ ही अन्य महिलाएं मंगल गीत गाते हुए कुआं के पास पहुंचती हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

महुआ ने लोकसभा अध्यक्ष पर निष्क्रियता का लगाया आरोप

नईदिल्ली। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने

गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि लोकसभा की सभी उचित प्रक्रिया और नियम पूरी तरह से विफल हो गए हैं। कैश-फॉर-क्वेरी घोटाले में लोकसभा की आचार समिति की मसौदा रिपोर्ट तक मीडिया की पहुंच होने का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पीकर पर निष्क्रियता और मेरी पिछली शिकायतों पर प्रतिक्रिया की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने बिड़ला को लिखे पत्र में कहा कि स्पष्ट रूप से लोकसभा की सभी उचित प्रक्रिया और नियम पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। आपकी निष्क्रियता और मेरी पिछली शिकायतों पर प्रतिक्रिया की कमी भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया ने कल खबर दी कि पैनल व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के साथ संसद के आधिकारिक पोर्टल की लॉगिन क्रेडेंशियल कथित तौर पर साझा करने के लिए मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश करेगा, क्योंकि यह अनैतिक आचरण है।

नीतीश अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं: हिमंता

खंडवा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में

भाजपा के लिए प्रचार करने के लिए खंडवा पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने नीतीश विवाद में प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ने का सलाह दी है। सीएम सरमा ने नीतीश द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में महिलाओं के प्रति की गई विवादित टिप्पणी पर कहा कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और वो बिहार के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने तत्काल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की भी मांग की। सीएम सरमा ने खंडवा में कहा, नीतीश कुमार के बयान से मुझे लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड को तत्काल उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए क्योंकि खोए हुए मानसिक संतुलन वाला मुख्यमंत्री राज्य के लिए बड़ा खतरा है।

नीतीश अपने मन की गंदगी घर तक रखें : नवनीत राणा

मुंबई। महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा

की सांसद नवनीत राणा ने नीतीश विवाद में बेहद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो अब मुख्यमंत्री पद के काबिल नहीं रह गये हैं, इसलिए उन्हें तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सांसद नवनीत राणा ने कहा, आपको बिहार की महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करनी चाहिए। अपने मन की सारी गंदगी अपने घर तक ही सीमित रखें। हमें आपकी माफी नहीं चाहिए, आपको अपना इस्तीफा देना चाहिए। बीते मंगलवार को बिहार विधानसभा में जाति जनगणना पर बहस के दौरान सीएम नीतीश ने राज्य में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए लड़कियों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए अजीब टिप्पणी की। इसके बाद शुरू हुए भाजपा के तीखे हमलों को देखते हुए नीतीश कुमार ने बुधवार को विधानसभा में की गई अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी मांग ली।

प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा

सदन में जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में दिए गए विवादित बयान का मामला ठंढा पड़ता नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार अपने बयान के लिए भले ही माफी मांग चुके हों लेकिन राजद और जदयू के अन्य नेता लगातार उनका बचाव करने में जुटे हैं। राज्य के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी नीतीश के बयान का बचाव किया था जिसके बाद वह पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के निशाने पर आ गए हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विवादास्पद टिप्पणी का बचाव करने के लिए प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को आड़े हाथों लिया और कहा कि तेजस्वी को यौन शिक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वह स्कूल नहीं गए। लोग जानते हैं कि उन्होंने 9वीं कक्षा भी पास नहीं की है। तेजस्वी पर बरसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के उपमुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से खुलासा करना चाहिए कि उन्होंने किस स्कूल में पढ़ाई की और कहां से यौन शिक्षा प्राप्त की।

ईडी के सामने पेश हुए अभिषेक बनर्जी

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के सांसद

अभिषेक बनर्जी कथित बंगाल स्कूल रोजगार घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता कार्यालय में पेश हुए। इससे पहले ईडी ने अभिषेक बनर्जी को तलब किया था। उन्हें 9 नवंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था। ईडी कार्यालय से बाहर आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैंने कथित स्कूल रोजगार घोटाले की जांच में सहयोग किया है। मैंने ईडी को छह हजार पन्नों का जवाब सौंपा है। अभिषेक ने कहा कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वे जब चाहें मुझे बुला सकते हैं। सभी चीजें लोगों के सामने हैं कि भाजपा हमसे लड़ने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो अदालत के सामने पेश करें।

मध्यप्रदेश को मोदी की गारंटी पर भरोसा, कमलनाथ और दिग्विजय दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे

देश का पैसा गरीबों के काम आ रहा है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब घोटाले होते थे: मोदी

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि आपका एक वोट भाजपा को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने, दिल्ली में मोदी को मजबूत करने और राज्य में कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने में मदद करेगा। सतना की रैली में मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने देश में गरीब लोगों को चार करोड़ पक्के मकान मुहैया कराए हैं। मैंने मुफ्त राशन योजना को अगले पांच साल तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि ये सतना की ही ताकत और सामर्थ्य है कि बंदूक की नली से संगीत के सुर निकलते हैं। विश्व जब संकटों के घेरे में है, चारो तरफ बम-बंदूक की आवाजें सुनाई दे रही है, भारत जैसे देश आज दुनिया में अपने विचार का प्रभाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे समय सतना की धरती से एक ऐसी ज्योति निकलती है जो बंदूक की नली से संगीत के सुर निकालती है। युद्ध की मानसिकता वाले मानव समुदाय को सतना की इस धरती का ये बहुत ही सशक्त संदेश है।

मोदी ने कहा कि मध्यप्रदेश के चुनाव में आपका हर वोट त्रिशक्ति की ताकत से भरा हुआ है। आपका एक वोट यहां फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रहा है। आपका वही वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा। आपका वही वोट, भ्रष्टाचारी कांग्रेस को मध्यप्रदेश की सरकार से सौ कोस दूर रखेगा। यानी एक वोट, तीन कमाल! उन्होंने कहा कि अभी यहां मतदान में इतने दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही झूठ का गुब्बारा फुट गया है। कांग्रेस के पास मध्यप्रदेश के विकास का कोई रोडमैप नहीं है। कांग्रेस के थके-हारे चेहरों में मध्यप्रदेश के युवाओं को कोई भविष्य नहीं दिखता। इसलिए मध्यप्रदेश को भाजपा पर भरोसा है। मध्यप्रदेश को मोदी की गारंटी पर भरोसा है।

नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मैं आजकल जहां भी जाता हूं, वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार-बार आती है। वो

बात मुझे आंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती रहती है। वो बात है - राम काज कीन्हें बिनु, मोहि कहां विश्राम... अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र का भव्य मंदिर नया संसद भवन बनते हैं, तो हम 30 हजार पंचायत भवन भी बनाते हैं। मुझे खुशी है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार होने के कारण मध्यप्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां गरीबों के लिए लाखों घर बनाए गए। यहां सतना में भी गरीबों को 1.32 लाख घर मिले हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों का घर हो, मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो आज इन पर भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपये खर्च कर रही है अर्थात देश का पैसा गरीबों के काम आ रहा है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, तब देश के लाखों करोड़ रुपये 2जी घोटाले, कोयला घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाले और हेलिकॉप्टर घोटाले में जाते थे। मोदी ने ये सारे घोटाले बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने घोटाले भी बंद किए और कांग्रेस के करप्शन काल में जो बिचौलियों की मौज थी, उसको भी बंद करा दिया। भाजपा सरकार ने सरकारी योजनाओं का पैसा गरीबों के बैंक खातों में ट्रांसफर करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने आपके सामने 2 ऐसे नेता खड़े किए हैं, जो कई दशकों से मध्य प्रदेश कांग्रेस को चलाते हैं। आजकल वो दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। यही नेता मध्यप्रदेश को दशकों तक अभाव में रखने के लिए जिम्मेदार हैं। ये आपके बेहतर भविष्य का भरोसा नहीं दे सकते। इनका तो अभी बस एक ही एजेंडा है कि 3 दिसंबर को भाजपा से हारने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस पर किसका बेटा कब्जा करेगा! अपने बेटों को सेट करने के लिए वो पूरे मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हैं।

मैंने कांग्रेस की दुकान बंद करा दी

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके चेले चपाटों को इतना बड़ा नुकसान हो गया, भ्रष्टाचार की काली कमाई को रोक दिया तो वो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे। ये जो गालियां पड़ रहीं हैं ना उसका कारण यही है। मैंने दुकान बंद करा दी। आपने चौकीदार को दिल्ली में बिठा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पर्यटन के क्षेत्र में सतना में बड़ा काम कर रही है। तीन दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद सभी विकास कार्यों के लिए काम तेज हो जाएगा। पहली बार वोट देने वाले युवाओं से कहना चाहता हूं कि इस चुनाव को लीड आप कीजिए। ये विधायक चुनने का नहीं अपना भविष्य चुनने का चुनाव है। भाजपा कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता मेरे लिए श्रद्धेय है।

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए पूरा देश दिल्ली से शुरू होता था और दिल्ली में ही खत्म हो जाता था। कांग्रेस के नेता विदेशी दोस्तों को भारत की गरीबी दिखाने के लिए ले जाते थे। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब एक मजाक बन गया था। कांग्रेस के नेता जिन झुग्गियों में फोटो खिंचाकर वापस आ जाते थे, उन गरीबों को आज मोदी पक्के घर दे रहा है। आज बच्चों को पोषण की चिंता ये गरीब का बेटा मोदी कर रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस देश को पीछे ले जाएगी। कांग्रेस ने वर्षों तक महिला आरक्षण कानून को लटकाकर रखा। जब हम तीन तलाक पर बिल लेकर आये कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था।

राहुल का पीएम मोदी पर निशाना

देश में सिर्फ एक जाति गरीब, तो खुद को क्यों कहते हैं ओबीसी

रायपुर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और पूछा कि वह खुद को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में क्यों बताते रहते हैं जबकि प्रधानमंत्री भारत में जिस एकमात्र जाति को गरीब मानते हैं। छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि पीएम मोदी हर भाषण में कहते हैं, मैं ओबीसी हूं। लेकिन जब मैं जाति जनगणना के बारे में बात करता हूं, तो वे कहते हैं कि भारत में कोई जाति नहीं है। भारत में केवल एक ही जाति है- गरीब। राहुल ने पूछा कि मोदी जी, अगर देश में गरीब ही एकमात्र जाति है तो आप खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं?

इसके बाद उन्होंने काले धन, नोटबंदी या पहले रद्द किए गए कृषि कानूनों के बारे में किए गए वादों के लिए पीएम मोदी पर कटाक्ष किया और कहा कि वे या तो झूठे थे या कभी पूरे नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए और आपको 15 लाख रुपये देने का वादा किया. क्या आपने इसे प्राप्त किया था? उन्होंने कहा कि नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ? उन्होंने कहा कि कृषि बिल से किसानों को फायदा होगा. किसानों ने खुद ही बिल को खारिज कर दिया। आप जानते हैं कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि पिछले चुनाव के दौरान किसानों की कर्जमाफी समेत छत्तीसगढ़ के लोगों से उन्होंने जो भी वादे किए थे, उन्हें राज्य की भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पूरा किया है। मैंने पिछले चुनाव में कहा था कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। लिख लीजिए, इस बार माफ होगा। पिछली बार हमने कहा था, बिजली बिल हाफ। इस बार खपत का बिजली बिल 200 यूनिट तक की बिजली माफ कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ के 40 लाख परिवारों को बिजली

के लिए एक पैसा भी नहीं देना होगा।

राहुल गांधी ने जाति जनगणना के मुद्दे पर मोदी को घेरा

राहुल गांधी आज अशोकनगर जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने नई सराई में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि ये एक दूसरे को धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। राहुल ने कहा कि दो सरकारें चलती हैं एक गरीबों की मदद करती है एक बिजनेसमैन की मदद करती है। आपका पैसा मोदी जी अडानी को देते हैं और अडानी दुबई में जाकर बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। जाति जनगणना इन सभी से निपटने का तरीका है, जिसे मैं एक्स-रे कहता हूं। जिस दिन जाति जनगणना होगी उस दिन मध्यप्रदेश के लोगों को पता चल जाएगा कि लोग बेरोजगार क्यों हैं। मैं मोदी जी से कहता हूं जाति जनगणना के लिए तो मोदी जी कहते हैं कि जात तो है ही नहीं। अपने आप को ओबीसी कहते हैं, लेकिन जब जाति जनगणना की बात होती है तो कहते हैं जाति तो एक ही है, गरीब हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

टीम इंडिया के सामने पहला सेमीफाइनल में कौन ?

नईदिल्ली। 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े

स्टेडियम में विश्व कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा सेमीफाइनल के लिए टीम इंडिया ने पहले से ही अपनी जगह सुनिश्चित कर रखी है। लेकिन भारत के सामने वानखेड़े में कौन सी टीम सामने होगी। इस पर अभी भी संशय बना हुआ। हालांकि, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। इधर, प्वाइंट टेबल में चौथे पायदान पर आने के लिए और भारत के साथ सेमीफाइनल खेलने के लिए तीन टीमों के भाग्य का फैसला बचे हुए आखिरी मैच में होने वाला है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों टीमों के पास 8-8-8 अंक है। विश्व कप में चार टीमों के बीच सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। तीन टीम मिल चुकी है। भारत पहले पायदान पर, साउथ अफ्रीका दूसरे पायदान पर तीसरे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया है। चौथे पायदान के लिए तीन टीमों में अभी जंग चल रही है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका मैच पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नजर भी बनी रहेगी। न्यूजीलैंड ने विश्व कप 2023 में शानदार शुरुआत की थी। टीम ने अपने पहले चार मैच में जीत दर्ज कर प्वाइंट टेबल में नंबर-1 की जगह बनाई। लेकिन भारत के साथ जो हार का सिलसिला शुरू हुआ वह अभी भी जारी है। न्यूजीलैंड ने 8 मैच में 4 जीत 4 हार के साथ चौथे स्थान पर है। रन रेट +0.3968। वहीं पाकिस्तान ने 8 मैच में चार जीत चार हार के साथ 8 अंक +0.036 रन रेट के साथ पांचवे स्थान पर बनी हुई है। वही, ऑस्ट्रेलिया से अपना पिछला मुकाबला हार चुकी अफगानिस्तान 8 मैच में चार जीत चार हार के साथ 8 अंक और रन रेट -0.338 के साथ छठे स्थान पर बनी हुई है। पाकिस्तान का अगला मुकाबला 11 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ होना है। वहीं, अफगानिस्तान का अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ होना है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 143 अंक टूटा निफ्टी 19,400 के करीब

नईदिल्ली। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 143 अंक कमजोर हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 42 अंक की गिरावट दर्ज की गई। व्यापक बाजारों में, बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में क्रमश: 0.26 प्रतिशत और 0.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 143.41 अंक यानी 0.22 फीसदी की गिरावट के साथ 64,832.20 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 65,046.56 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 64,768.76 तक आया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 42.30 अंक यानी 0.22 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 19,401.20 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 19,463.90 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 19,378.35 तक आया।

अमेरिकी बाजारों में मेड इन इंडिया की बढ़ी लोकप्रियता

वाशगिंटन। कोरोना महामारी के कारण वैश्विक बाजारों की हालत धीरे-धीरे सुधर रही है। हाल के दिनों में वैश्विक बाजार में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं जिसका फायदा भारत को होता नजर आ रहा है। दरअसल, चीन की कीमत पर विनिर्माण, सोर्सिंग और आपूर्ति श्रृंखला में हाल के वैश्विक बदलावों से भारत धीरे-धीरे लाभ उठा रहा है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक हालिया अध्ययन में बताया गया है कि चीन से अमेरिकी वस्तुओं के आयात में मुद्रास्फीति-समायोजित शर्तों के अनुसार 2018 से 2022 तक 10% की गिरावट आई, वे भारत से 44%, मैक्सिको से 18% और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के 10 देशों से 65% बढ़ गए। उदाहरण के लिए, चीन से अमेरिकी यांत्रिक मशीनरी का आयात 2018 से 2022 तक 28% कम हो गया।

अदाणी पोर्ट्स की दूसरी तिमाही का नेट प्रॉफिट 1.37% बढ़ा

नईदिल्ली। अदाणी समूह की कंपनी अदाणी

पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपी-सेज) का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 1.37 प्रतिशत बढ़कर 1,761.63 करोड़ रुपये रहा है। अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन ने गुरुवार को बीएसई यह सूचना दी। एक साल पहले 2022-23 की इसी तिमाही में कंपनी ने 1,737.81 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। कंपनी की कुल आय सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही में 6,951.86 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 5,648.91 करोड़ रुपये थी। एपी-सेज का कुल व्यय भी बढ़कर आलोच्य तिमाही में 4,477 करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले 2022-23 की दूसरी तिमाही में 3,751.54 करोड़ रुपये था।

मूडीज ने भारत के ग्रोथ अनुमान को 6.7% पर रखा

नईदिल्ली। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.7 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। मूडीज का मानना है कि देश में मजबूत घरेलू मांग की वजह से निकट भविष्य में वृद्धि की रफ्तार कायम रहेगी। प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण निर्यात कमजोर रहने से मूडीज ने अपने 'वैश्विक वृहद आर्थिक परिदृश्य-2024-25' में कहा कि घरेलू मांग में सतत बढ़ोतरी भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। मूडीज ने कहा, ''हमें उम्मीद है कि भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 2023 में करीब 6.7 प्रतिशत, 2024 में 6.1 प्रतिशत और 2025 में 6.3 प्रतिशत बढ़ेगी।'' भारत की आर्थिक वृद्धि दर जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत रही है, जो मार्च तिमाही में 6.1 प्रतिशत थी।

उत्तराखंड राज्य के 23 साल और आर्थिक उतार-चढ़ाव

जयसिंह रावत

नवगठित उत्तंराचल की अंतरिम सरकार के पहले वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 3 मई 2001 को जब राज्य का पहला बजट पेश किया था तो उसमें कुल व्यय 4,505.75 करोड़ और राजस्व प्राप्तियों 3,244.71 करोड़ प्रस्तावित थीं। राज्य गठन के समय उत्तरांचल को लगभग 1,750 करोड़ का घाटा विरासत में मिला था और अंतरिम सरकार ने 10 करोड़ के ओवर ड्राफ्ट के साथ अपना काम शुरू किया था। यही नहीं नए राज्य को विरासत में भारी-भरकम कर्ज भी मिला था। जबकि 15 मार्च 2023 को मौजूदा वित्त मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने 2023-24 का सालाना बजट पेश किया तो उसमें कुल व्यय 77407.08 करोड़ और राजस्व प्राप्तियां 76,592.54 करोड़ प्रस्तावित थीं।

उत्तरांचल के नाम से जन्म लेने वाले उत्तराखण्ड के बजट की इतनी बड़ी छलांग नए राज्य की प्रगति का एक पैमाना ही है। हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता और केदारनाथ की जैसी आपदाएं न आतीं तो यह राज्य इससे भी कहीं अधिक तरक्की कर चुका होता। लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद अभी उत्तराखण्डवासियों के कुछ सपने अधूरे हैं तो कुछ बिखर भी गए हैं।

उत्तराखण्ड के जन्म के समय राज्य को विरासत में भारी भरकम घाटा और कर्ज मिलने के साथ ही 11वें वित्त आयोग से भी पूरा न्याय नहीं मिला था। इन भारी रुकावटों के बावजूद केन्द्र की तत्कालीन बाजपेयी सरकार ने अन्य हिमालयी राज्यों के साथ ही उत्तरांचल को भी 1 मई 2001 को विशेष श्रेणी का दर्जा दे दिया जिससे विकास के मार्ग में आने वाली वित्तीय कठिनाइयां काफी आसान हुईं। इसके बाद राज्य को औद्योगिक

पैकेज भी मिला, जिससे राज्य का तेजी से औद्योगिक विकास होने के साथ ही राज्य की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती गई। सन् 2002 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में 12वां वित्त आयोग गठित हुआ तो तत्कालीन सरकार के होम वर्क के फलस्वरूप न केवल 11 वें आयोग के नुकसान की काफी हद तक भरपाई हुई बल्कि अपेक्षा के अनुरूप आयोग ने नए राज्य पर दरियादिली भी दिखाई।

1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का टैग उतारकर उत्तराखण्ड नाम धारण करने वाले इस राज्य की विकास यात्रा में राजनीतिक अस्थिरता, पद लोलुपता और केदारनाथ जैसी आपदाओं के कारण व्यवधान अवश्य रहे फिर भी विशेष श्रेणी का दर्जा, औद्योगिक पैकेज और नये राज्य के प्रति केन्द्र सरकारों की सहानुभूति के चलते इन 23 सालों में राज्य की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय ने भी आश्चर्यजनक छलांगें लगाईं।

नवीनतम अनुमान के अनुसार राज्य की जीडीपी 3.33 लाख करोड़ और प्रति व्यक्ति आय 2,33,565 तक पहुंच गई है। जबकि 1999.2000 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय मात्र 14,086 रुपये और जीडीपी लगभग 1.60 लाख करोड़ के आसपास थी। यद्यपि टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख तक भी नहीं पहुंची। जबकि हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय उत्तराखण्ड से कम 2,22,226.54 तक ही पहुंची है। इसी प्रकार हिमाचल की जीएसडीपी भी उत्तराखण्ड की कहीं कम 2.14 लाख करोड़ है, वहां बैंकों का ऋण जमानुपात भी उत्तराखण्ड से बहुत कम 30.80 है। राज्य गठन के समय विद्युतीकृत गावों की संख्या 12519 थी जो कि अब 15745 तक पहुंच गई है। कम से कम बिजली के खंभे तो गांवों में पहुंच ही गए, चाहे उन पर बिजली हो या नहीं।

सन् 2002 में जब पहली निर्वाचित सरकार ने सत्ता संभाली तो उस समय बैंको का ऋण जमा अनुपात मात्र 19 था। मतलब यह कि बैंक जनता से 100 रुपये जमा करा रहे थे तो मात्र 19 रुपये यहां कर्ज दे रहे थे और बाकी धन का कहीं और व्यवसायिक उपयोग कर रहे थे। आज की तारीख में यह ऋण जमा अनुपाल 51 तक पहुंच गया है। जाहिर है कि 100 में 51 रुपये यहीं लोगों को काम धन्धे चलाने के लिए दिए जा रहे हैं। हालांकि पहाड़ों में यह ऋण जमा अनुपात अब भी चिन्ताजनक स्थिति में हैं।

छत्तीसगढ़वासी कांग्रेस के झूठ से बचें : जयराम ठाकुर

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर ने रायपुर भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा की कांग्रेस ने न हिमाचल में वादे पूरे किए न छत्तीसगढ़ में कांग्रेस झूठे वादे करने में माहिर है।उन्होंने कहा

झूठी कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ में झूठी गारंटी बांट रही है। कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी ठग है जो झूठ बोलकर छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई और झूठ बोलकर हिमाचल प्रदेश की सत्ता हासिल की। कांग्रेस ने न तो छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में किए गए वादे निभाए और न ही हिमाचल में दी गई पांच गारंटियों में से अब तक एक भी गारंटी पूरी की है। जिस तरह कांग्रेस झूठी है, उसी तरह उसकी गारंटी भी झूठी है। छत्तीसगढ़ की जनता झूठी गारंटियों के छलावे में आने से बचे। भाजपा उसे बेहतर भविष्य की गारंटी दे रही है।कांग्रेस ने हिमाचल की जनता को धोखा देने के लिए जो पांच गारंटी दी थीं, उनमें पहले गारंटी यह है कि महिलाओं को हर महीने 15 सौ रुपए देने का वादा किया गया था। लेकिन महिलाओं को एक पैसा भी नहीं मिला। ठीक वैसे ही, जैसे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं से पेंशन और मुफ्त सिलेंडर का वादा किया था और वादा खिलाफी की। कांग्रेस ने दूसरी गारंटी यह दी थी कि बेरोजगारों को 5 लाख नौकरियां देंगे लेकिन 11 माह बाद भी बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिली है।कांग्रेस ने हिमाचल में तीसरी गारंटी यह दी थी कि हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी लेकिन यह वादा भी नहीं निभाया गया।

कांग्रेस ने हिमाचल के पशुपालकों को गारंटी दी थी कि उनसे 100 रुपये किलो की कीमत पर दूध खरीदेंगे। पशुपालक अब तक इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की हिमाचल सरकार उनसे 100 रुपये किलो के दाम पर दूध कब खरीदेगी।कांग्रेस ने हिमाचल के किसानों से झूठ बोला था कि उनसे 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा जाएगा। कांग्रेस की सरकार ने अब तक 2 ग्राम गोबर भी नहीं खरीदा है।झूठी कांग्रेस ने हिमाचल में अन्य झूठी गारंटी भी दी थीं, जिनमें कहा गया था कि बागवान फलों की कीमत तय करेंगे, युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड रखा जाएगा, हर विधानसभा क्षेत्र में चार अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, हर गांव में मोबाइल क्लीनिक से मुफ्त इलाज होगा। लेकिन यह सारे वादे कांग्रेस भूल गई। उसकी नीयत में खोट है।

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की तरह हिमाचल प्रदेश में भी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का वादा किया था। यह भी पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस की सारी गारंटी झूठ का पुलिंदा है।कांग्रेस की ओर से हिमाचल की जनता को झूठी गारंटी बांटने वालों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थीं। भूपेश बघेल ने जिस तरह 5 साल पहले छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा, वैसे ही हिमाचल जाकर भी वहां की जनता को छला है। अब भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ की जनता को जो गारंटी बांट रही हैं, वे सब की सब झूठी हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि कांग्रेस में 2018 के चुनाव में जो 36 वादे किए थे, उनमें से एक तिहाई वादे भी ढंग से पूरे नहीं किए हैं। जो किया है उसमें छलावे के अलावा कुछ भी नहीं है।

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, था लेकिन सरकार के अंतिम समय में मुट्ठी भर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर औपचारिकता की है। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार राज्य के बेरोजगारों का 15 हजार करोड़ रुपए डकार गई।कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में शराब बंदी का वादा किया था लेकिन 5 साल तक शराब घोटाला करने में लगी रही।200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट नही बनाए,20 लाख का मुफ्त इलाज नही दिया,संपत्ति कर माफ नही किया,बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया,नियमतीकरण नही किया कांग्रेस के सभी वादे झूठे निकले।

छत्तीसगढ़ में घोटाले की सरकार ने वादे निभाने की जगह केवल घोटाले किए हैं। इन सभी घोटालों से छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह परिचित है। उसे मालूम है कि किस घोटाले में कितने करोड़ का खेल भूपेश बघेल ने किया है।

उन्होंने कहा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और हिमाचल दोनो जगह झूठ बोलकर सरकार बनाई छत्तीसगढ़ वासी सचेत रहे,अब इनकी बातों में न आए।प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी,सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल माजूद रहे,यूपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला और भाजपा नेता सुरेंद्र पाटनी माजूद रहे।

दिवाली मिलन एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए बृजमोहन

रायपुर के श्रमजीवी कारीगरों को बृजमोहन ने किया सम्मानित

■ 800 श्रमजीवियों ने किया भाजपा प्रवेश।

रायपुर। वरिष्ठ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने समाजिक संस्था उपासना सेवा फाउंडेशन द्वारा आयोजित श्रमजीवी कारीगरों के दिवाली मिलन एवं सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।

इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में शहर में काम करने वाले कर्मवीर प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर,न्यूज पेपर हाकर,आटो चालक, टाटा एस चालक, इलेक्ट्रीशियन,मिस्त्री हलवाई काम करने वाली महिलाएं, घरों में काम करने वाली बाई, टैक्टर चालको को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर बृजमोहन ने कहा कि भाजपा की सरकार आने पर महतारी वंदन योजना के तहत साल में 12000 रुपया का आर्थिक लाभ, गरीबों को पक्का मकान, हर घर नल से जल, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 10 लाख तक का मुफ्त इलाज़ आदि का लाभ दिलाने की बात कही।

समारोह में उपस्थित लोगों ने भी बृजमोहन अग्रवाल को आठवीं बार जीत का भरोसा दिलाया।

इस कार्यक्रम में विशेष रूप से डा.सुरेन्द्र शुक्ला , उमेश अग्रवाल, निश्चय वाजपेई, टीकम साहू, दद्दू देवांगन,निलेश अग्रवाल विनय साहू, स्नह किशोर सिन्हा, प्रफुल्ल अग्रवाल, बसंत गौड़ और उपासना सेवा फाऊंडेशन के अध्यक्ष रतिकांत साहू दिलीप यदु, विवेक वर्धन जी सूरज यादव सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर 800 लोगो ने भाजपा प्रवेश करते हुए बृजमोहन अग्रवाल पर भरोसा जताते हुए भाजपा जिताने का संकल्प लिया।

सिद्धार्थनाथ ने मेरी मानहानि की है, बदनाम करने का षडयंत्र: विनोद वर्मा

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने मेरी मानहानि की है। भाजपा के दो प्रदेश प्रवक्ता भी इसमें शामिल हैं। जानबूझकर बदनाम करने का षडयंत्र किया गया है। चेतावनी देते हुए कहा कि वे लोग माफी मांगें या मुकदमा के लिए तैयार रहें।

उन्होंने कहा कि महादेव ऐप की जांच का काम छत्तीसगढ़ पुलिस ने शुरु किया। अब तक 72 मामले दर्ज किए गए हैं और 449 लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है।191 लैपटॉप, 865 मोबाइल फ़ोन और डेढ़ करोड़ से अधिक की संपत्ति और 16 करोड़ रुपए बैंक खातों में जब्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में दर्ज मामलों के आधार पर ही प्रत्यावर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जांच शुरू की है। रायपुर पुलिस के साइबर सेल ने 12 अक्टूबर 2022 को गूगल को एक पत्र लिखकर कहा था कि महादेव ऐप गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है, चूंकि भारत में जुआ खेलना अपराध है। इस ऐप के माध्यम से जुआ खिलवाया जा रहा है, इस ऐप को बंद कर दिया जाए और इस ऐप को बनाने और चलाने वालों के नाम पुलिस को बताए जाएं। इस पत्र के बाद गूगल ने महादेव ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने ही जांच के बाद पाया कि महादेव ऐप के संचालक रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर हैं। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया। इसके बाद से लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कह रहे हैं कि इन अपराधियों को केंद्र सरकार गिरफ़्तार करे क्योंकि वे इस देश में नहीं रहते और छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि वे किसी अपराधी को किसी दूसरे देश से गिरफ्तार करके लाएं। महादेव ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी उन्होंने कई बार की है। उन्होंने आशंका जाहिर की थी कि ऐप पर रोक इसलिए नहीं लग रही है कि क्योंकि भाजपा के लोगों से संचालकों की सांठगांठ हो गई है।ईडी ने अब तक इस मामले में जिस तरह की कार्रवाई की है उससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं. एक अनजान व्यक्ति के बयान पर ईडी ने प्रेस नोट जारी कर दिया कि वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पैसे पहुंचाता था.अभी इस बात की जांच बाक़ी है कि इस बयान का सच क्या है।

फाफाडीह क्षेत्र में पुरंदर मिश्रा का गर्मजोशी से किया स्वागत

■ लोगों का समर्थन बता रहा है भाजपा के प्रति विश्वासः पुरंदर मिश्रा

रायपुर। रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने गुरुवार को सुबह सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ भाजपा मंडल फाफाडीह क्षेत्र का धुआंधार दौरा किया। जनसंपर्क की शुरुआत उन्होंने जागृति नगर वाल्टेयर लाइन से की। इस बीच अंडरब्रिज से कालीनगर मुख्य मार्ग पर उत्साही समर्थकों ने जगह-जगह श्री मिश्रा का स्वागत किया। फूलमाला पहनाई। चुनाव में जीत के लिए नेताओं में भी जबर्दस्त जुनून है। संबंधित क्षेत्र का ऐसा कोई कोना नहीं छूट रहा है, जहां तक नेता न पहुंच पा रहे हों। इसी बीच रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा भी सुबह-शाम दौरा और जनसंपर्क कर रहे हैं। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ भी लगातार उनके साथ चल रही है।

भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने कहा, इस बार महिलाएं खुलकर कमल छाप को वोट देने वाली हैं। भाजपा के घोषणा पत्र में मादी ने जो गारंटी दी हैं, उसमें हर महिला को सालाना 12000 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, बेटी के जन्म में 1.50 लाख रुपए जमा कराने जैसे वायदों को महिलाओं का भारी जनसमर्थन मिल रहा है।उन्होंने आगे कहा, रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अपने-अपनो से मुलाकात होने से मैं बेहद आनंदित तो हूं ही, धन्य भी हो रहा हूं। चुनाव के लिहाज से मैं आप सबसे एक और बात साझा करना चाहता हूं कि, विकास के दृष्टिकोण से लक्ष्य काफी बड़ा है और इसे पूरा करने के लिए जनता का आशीर्वाद मिलना आवश्यक है, जिसमें आप सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

भाजपा संवारेगी छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्यः साव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश की प्रतिभासम्पन्न युवा शक्ति के साथ कदम-कदम पर किए गए छलावे को लेकर कांग्रेस की भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। श्री साव ने कहा कि बेरोजगारी भत्ते से लेकर रोजगार तक, प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर खेल के मैदान तक हर जगह युवाओं के साथ छल-कपट की जो मिसाल कांग्रेस सरकार ने पेश की है, उससे युवाओं में गहन आक्रोश नजर आ रहा है और मतदान के प्रथम चरण में इसका साफ संकेत मिल रहा है। श्री साव ने कहा कि युवाओं की प्रतिभा का सम्मान कर उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का संकल्प भाजपा ने लिया है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के 15 वर्षों के कार्यकाल में युवाओं के सर्वतोमुखी विकास के लिए काफी कार्य हुए थे। भाजपा शासनकाल में अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए 27 जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज शुरू किए। छत्तीसगढ़ कौशल के अधिकार% को मौलिक प्रावधान के साथ %छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला 2013 में देश का पहला राज्य बना। भाजपा के कार्यकाल में कई खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू और पूरी की गई। श्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2023 तक छत्तीसगढ़ में कुल 85,083 कर्मचारियों के साथ 2,949 प्रतिष्ठान लाभान्वित हुए हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

कांग्रेस का घोषणा पत्र विजन डॉक्यूमेंट होता है: बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वह करती है। कांग्रेस का घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ को स्वस्थ, समृद्ध और शिक्षित बनाने का वायदा करता है। 2018 में कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में किसान, आदिवासी, युवाओं, महिलाओं सभी से वायदा किया था और उसको पूरा किया। 2023 में हमारे घोषणा पत्र में हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा गया है। जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र और उनको किये गये वायदों को गंभीरता से लेती है तथा उस पर भरोसा भी करती है जनता जानती है कांग्रेस का घोषणा पत्र उसकी सरकार विजन डॉक्यूमेंट होता है। हम आम आदमी को सशक्त बनाने योजना लेकर आगे बढ़ रहे है।2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहले ही घंटे में कांग्रेस की सरकार ने घोषणा पत्र को पूरा करना शुरू कर दिया था। लगभग 20 लाख किसानों का लगभग 10 हजार करोड़ कर्ज माफ किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यसचिव को बुला कर कांग्रेस का जन घोषणा पत्र देकर यह सुनिश्चित करने को कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के हर वायदे को पूरा करने हेतु कार्य योजना बनाया जाये इसी का परिणाम था कि पांच साल में भूपेश सरकार ने 36 में से 98 प्रतिशत वायदों को पूरा कर दिखाया।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि पहले की तरह इस बार भी होगा।

दस्तावेज दिखाकर भी मतदाता कर सकेंगे मतदान

बिलासपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारीअवनीश शरण ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। कलेक्टर ने बताया कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए हैं। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत हैं।

चुनाव हारता देख बृजमोहन नौटंकी कर रहे : शुक्ला

रायपुर। भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल द्वारा अपने ऊपर हमले के दावों को प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है, यह चुनाव हारते हुये प्रत्याशी की नई नौटंकी है। बृजमोहन अग्रवाल का सारा चुनावी मैनेजमेंट महंत रामसुंदर दास की सरलता और निश्छलता के सामने फेल हो गया है। बृजमोहन अग्रवाल का

दक्षिण से चुनाव हारना तय है, दक्षिण की जनता ने अबकी बार बृजमोहन से छुटकारा पाने का मन बना लिया है। दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशी महंत रामसुदंर दास सरल सहज और सहृदयी संत है। वे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े धर्म गुरू है। उनकी मृदुभाषी आचरण से रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मतदाता उन्हें हाथों हाथ ले रहे, क्षेत्र के महिला, पुरूष सभी महंत जी की जीत सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है। दक्षिण क्षेत्र में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनाव प्रचार कार्यक्रम भी था। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उमड़े जनसैलाब महंत श्री रामसुंदर दास को मिल रहे जनसमर्थन से बृजमोहन अग्रवाल बौखला गये है। बौखलाहट में वे सहानुभूति पाने नौटंकी कर रहे है।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास की लोकप्रियता के सामने बृजमोहन और भाजपा अपना पसंदीदा सांप्रदायिकता का गंदा खेल भी नहीं खेल पा रही है।

भाजपा प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने मेरी मानहानि की है: वर्मा

रायपुर। पुलिस के साइबर सेल ने 12 अक्टूबर 2022 को गूगल को एक पत्र लिखकर कहा था कि महादेव ऐप गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है, चूंकि भारत में जुआ खेलना अपराध है और इस ऐप के माध्यम से जुआ खिलवाया जा रहा है, इस ऐप को बंद कर दिया जाए और इस ऐप को बनाने और चलाने वालों के नाम पुलिस को बताए जाएं।इस पत्र के बाद गूगल ने महादेव ऐप को गूगल प्ले स्टोर से

हटा दिया।छत्तीसगढ़ पुलिस ने ही जांच के बाद पाया कि महादेव ऐप के संचालक रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर हैं। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया। इसके बाद से लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी लगातार कह रहे हैं कि इन अपराधियों को केंद्र सरकार गिरफ़्तार करे क्योंकि वे इस देश में नहीं रहते और छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि वे किसी अपराधी को किसी दूसरे देश से गिरफ़्तार करके लाएं।महादेव ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी उन्होंने बार बार की। उन्होंने आशंका ज़ाहिर की थी कि ऐप पर रोक इसलिए नहीं लग रही है कि क्योंकि भाजपा के लोगों से संचालकों की सांठगांठ हो गई है।आखिरकार तीन दिन पहले केंद्र सरकार ने महादेव ऐप को बंद करने का दावा किया। लेकिन दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि उसी शाम एक समाचार चैनल ने दिखा दिया कि रोक लगाने की बात बेकार है क्योंकि ऐप तो बाक़ायदा चल रहा है और सट्टेबाज़ी का खेल निर्बाध रूप से जारी है।

आसमा को एक दशक के बाद मिला वोटिंग का अवसर

रायपुर। दक्षिण विधानसभा में टिकरापारा की रहवासी आसमा अशरफी आज अपनी खुशी बया नहीं कर पा रही थी, जब मतदान दल उनके घर वोट कराने पहुंचा उस समय वह बिस्तर मे थी क्योंकि उन्हे चलने फिरने में तकलीफ है। पहले उनके पहचान पत्र तथा रजिस्टर में हस्ताक्षर इत्यादि प्रक्रिया पूर्ण की गई। उसके बाद उन्होंने मतपत्र पर अपने मनपसंद अभ्यर्थी को गुप्त रुप से चिन्हाकित किया। फिर उसे फोल्ड कर मतपेटी में डाला। इसके बाद उनके चेहरे पर संतुष्टी के भाव उमड़ पड़े। साथ ही वह गौरवान्वित हो उठी की लोकतंत्र के महत्वपूर्ण क्षण का हिस्सा बन चुकी हुं। श्रीमती आसमा अशरफी बतातीं है उन्होंने शादी से पहले कटनी में वोट करने का मौका मिला था। शादी के कुछ वर्ष के बाद बीमार होने से चलने फिरने में तकलीफी होने लगी। इसके कारण वह मतदान केन्द्र तक जाकर वोट डालने में समर्थ नही थी। आज 13 साल बाद जब बीएलओ मेरे घर आई और होम वोटिंग के बारे में मुझे और मेरे परिजनों को बताया तो सहर्ष सहमति प्रदान की। मैने तो इससे पहले सोंचा ही नही था कि मै मतदान कर पाउंगी।

भाजपा के घोषणापत्र पर सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना

मोदी की गारंटी की नहीं है कोई गारंटी : भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के मोदी की गारंटी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने काला धन वापस लाने, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने, किसानों की आय दोगुनी करने, महंगाई कम करने समेत कई वादे किये थे जो आज तक पूरे नहीं हुए है। उन्होंने कहा कि जो 9 सालों में अपने वादों को पूरा नहीं कर पाया उसके गारंटी की कोई गारंटी नहीं है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कांग्रेस की घोषणा पत्र के आधार पर उपस्थित जनता को फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान

करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी चातुरी नंद को जिताने की अपील की।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रथम चरण में 20 सीटों पर हुए मतदान का जिक्र करते हुए कहा कि पहले चरण में शानदार मतदान हुआ है। जिस तरह की सूचना हमारे पास आ रही है वो बेहद ही उत्साहजनक है। 20 में से 19 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, एक सीट पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह का बचा है इस बार वो भी चुनाव हार रहे है। उन्होंने पूर्व सीएम पर कटाक्ष करते हुए कहा वे बुरी तरह से चुनाव हार रहे है, डॉ रमन सिंह का डब्बा गोल हो गया है।

गिनाई सरकार की उपलब्धियां

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सरकार के दौरान पिछले 5 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हमने किसानों से वादा निभाते हुए कर्जमाफ़ी की, हमने तेंदूपत्ता संग्राहकों से 4 हजार प्रति मानक बोरा की दर पर खरीदी की। हमने बच्चों को विश्वस्तरीय शिक्षा देने स्वामी आत्मानंद स्कूल शुरू किये जिससे हर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है। आमसभा में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस की घोषणओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिर से कांग्रेस की सरकार आते ही हम किसानों की कर्जमाफ़ी करेंगे।

निगरानी दलों ने अब तक जब्त की 66 करोड़ 33 लाख रुपये की नगदी और अन्य वस्तुएं

रायपुर. राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से 8 नवम्बर तक की स्थिति में 66 करोड़ 33 लाख रुपये की अवैध धन राशि और वस्तुएं जब्त की गई हैं. इनमें 17 करोड़ 98 लाख रुपये की नगद राशि शामिल हैं.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) द्वारा निगरानी के दौरान विगत 8 नवम्बर तक 47 हजार 371 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत एक करोड़ 35 लाख रुपये है. साथ ही तीन करोड़ 99

लाख रुपये कीमत की अन्य नशीली वस्तुएं भी जब्त की गई हैं. सघन जांच अभियान के दौरान 20 करोड़ 36 लाख रुपये कीमत के 484 किलोग्राम कीमती आभूषण और रत्न भी जब्त किए गए हैं. इनके अतिरिक्त अन्य सामग्रियां जिनकी कीमत 22 करोड़ 62 लाख रुपये है, भी जब्त की गई हैं.मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन दिशा-निर्देशों के परिपालन मंर राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन और संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है. प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निगरानी दलों द्वारा सघन जांच की कार्रवाई लगातार जारी है.

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.